PRGI Reg. No. : CTHIN/25/A1911

हिन्दी दैनिक

लोकतंत्र प्रहरी

● वर्ष-01 ● अंक- 247 ● भिलाई, शुक्रवार 10 अप्रैल 2026 ● हिन्दी दैनिक ● पृष्ठ संख्या-8 ● मूल्य - 2 रुपया ● संपादक- संजय तिवारी, मो. 9200000214

संक्षिप्त समाचार

पत्नी की हत्या कर बच्चे के साथ पति फरार

सिलीगुड़ी। माटीगाड़ा थाना क्षेत्र में एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है, जहां एक पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। तीन दिन बाद आज खुद ही पुलिस को फोन कर इसकी जानकारी दी। मृतका देबलिना बनर्जी पेशे से स्कूल शिक्षिका थीं, जबकि आरोपित पति बैंक कर्मचारी बताया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक, आरोपित पति अरिंद्र बनर्जी ने फोन कर बताया कि उसने अपनी पत्नी देबलिना बनर्जी की हत्या कर दी है और शव घर के अंदर पड़ा हुआ है। इसके बाद वह अपने 11 साल के बेटे को लेकर फरार हो गया। सूचना पाकर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और एक चार मंजिली इमारत के फ्लैट से महिला का शव बरामद किया, जो कंबल में लिपटा हुआ था। प्राथमिक जांच में आशंका जताई जा रही है कि हत्या रविवार दोपहर के बाद की गई। गला दबाकर हत्या किए जाने की संभावना है, हालांकि असली कारण का खुलासा पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के बाद ही होगा। डीसीपी काजी शमसुहीन अहमद ने बताया कि पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और फरार आरोपित की तलाश जारी है।

चुनाव से पहले कोलकाता के स्ट्रैंड रोड हथियारों का जखीरा मिला

कोलकाता। महानगर कोलकाता सहित पूरा बंगाल चुनावी गर्मी से तप रहा है। आरोप प्रत्यारोप का क्रम जारी है और इसी क्रम में महानगर कोलकाता से हथियारों का जखीरा मिलने से मतदान के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठना लाजमी है। आज दोपहर कोलकाता स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) ने कोलकाता के स्ट्रैंड रोड पर बिहार के रहने वाले एक नाबालिग मो. यूसुफ (17) से पांच हथियार बरामद किए। बरामद हथियारों में दो 7 एमएम पिस्तौलें शामिल हैं। इसके अलावा, 40 कारतूस भी ज़ब्त किए गए। यह 17 वर्षीय नाबालिग बिहार के नालंदा जिले का रहने वाला है। कोलकाता पुलिस की एसटीएफ फ़िलहाल इस बारे में और जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही है कि इस नाबालिग के पास ये हथियार कहां से आए। पुलिस को गुप्त सूत्रों से पहले ही खुफिया जानकारी मिली थी।

पश्चिम बंगाल की जनता को पीएम मोदी ने दी 6 गारंटी

पीएम मोदी बोले-बंगाल में अब हर रेपकांड की खुलेगी फाइल

हल्दिया/ एजेंसी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सरकार पर कुशासन का आरोप लगाते हुए उसकी कड़ी आलोचना की और आगामी विधानसभा चुनाव में मतदाताओं से तृणमूल कांग्रेस को सत्ता से बेदखल करने की अपील की। विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी का गढ़ माने जाने वाले हल्दिया में एक जनसभा को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि राज्य में सत्तारूढ़ दल बंगाल को पीछे धकेल रहा है। उन्होंने दावा किया, देश प्रगति के पथ पर अग्रसर है, जबकि तृणमूल कांग्रेस की 'निर्मम सरकार' बंगाल को पीछे धकेल रही है। 'विकसित बंगाल' की स्थापना के लिए यह जरूरी है कि पार्टी को सत्ता से हटाया जाए। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस ने बंगाल के युवाओं को दोहरा धोखा दिया। उसने निजी क्षेत्र और निवेश की संभावनाओं का नामोनिशान मिटा दिया है और सरकारी भितयों में तृणमूल के मंत्रियों ने लूट मचाई है तथा युवाओं के सपनों को कुचला है। औद्योगिक केंद्र में मोदी ने कहा, निवेश भय के माहौल में नहीं, बल्कि उस भरोसे के माहौल में आता है जो भाजपा बंगाल में लाएगी। उन्होंने तृणमूल कांग्रेस पर अपने वोट बैंक को सुरक्षित करने के लिए धर्म के आधार पर आरक्षण की नीति अपनाने का आरोप लगाया। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा,खराब मौसम के बावजूद हल्दिया रैली में लोगों की भारी उपस्थिति बंगाल में बदलाव का संकेत है। यह तृणमूल कांग्रेस के सत्ता से

बाहर होने का संकेत है। मोदी ने कहा, पांच साल पहले नंदीग्राम में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे इस बार भवानीपुर में दोहराए जाएंगे। अधिकारी ने 2021 में नंदीग्राम में ममता बनर्जी को हराया था और अब उनका मुकाबला दक्षिण कोलकाता के भवानीपुर स्थित उनके गढ़ में मौजूदा मुख्यमंत्री से है। तृणमूल कांग्रेस की आलोचना करते हुए मोदी ने कहा, ममता सरकार ने युवाओं के साथ जो किया, उसकी भरपाई अगले 100 साल में भी नहीं हो सकती। पश्चिम बंगाल में डबल इंजन वाली सरकार का समर्थन करते हुए प्रधानमंत्री ने जनसभा में कहा कि राज्य को प्रधानमंत्री का विरोध करने से कोई लाभ नहीं होगा, बल्कि तभी लाभ होगा जब प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री एक साथ मिलकर काम करेंगे। उन्होंने पश्चिम बंगाल की जनता से राज्य को मत्स्य पालन और समुद्री खाद्य क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का वादा किया, साथ ही इस बात पर प्रकाश डाला कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार ने मछुआरों के कल्याण के लिए एक समर्पित मंत्रालय की स्थापना की है और उनके लिए रिकॉर्ड बजट आवंटित किया है। पीएम मोदी ने कहा कि बंगाल की जमीन पर घुसपैठियों का कब्जा खतरनाक स्तर तक पहुंच गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि टीएमसी का सिंडिकेट घुसपैठियों को फर्जी सरकारी दस्तावेज दिलाने में मदद कर रहा है।

अंतिम गारंटी-सातवां वेतन आयोग के साथ घुसपैठियों पर बड़ा बयान

प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी अंतिम दो गारंटियों के जरिए समाज के दो अलग-अलग वर्गों को बड़ा संदेश दिया है। उन्होंने साफ किया कि जो लोग शरणार्थी के रूप में यहां रह रहे हैं, उन्हें संविधान के तहत हर अधिकार दिया जाएगा, लेकिन देश की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वाले घुसपैठियों को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और उन्हें बाहर निकाला जाएगा। इसके अलावा, राज्य के लाखों सरकारी कर्मचारियों और शिक्षकों के लिए उन्होंने एक बड़ी खुशखबरी दी है। मोदी ने छठी गारंटी देते हुए वादा किया कि भाजपा की सरकार बनते ही बंगाल में 'सातवां वेतन आयोग' लागू कर दिया जाएगा। अपनी बात खत्म करते हुए उन्होंने 23 अप्रैल को भारी संख्या में मतदान करने की अपील की ताकि हर बूथ पर कमल खिल सके।

चुनाव आयोग की बैठक में हाई-वोल्टेज ड्रामा!

चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से भिड़े ऑब्जर्वर अनुराग यादव

नई दिल्ली। एजेंसी

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले कोलकाता में एक उच्च स्तरीय चुनाव समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें माहौल काफी गर्म हो गया। विवाद उस समय बढ़ा, जब एक वरिष्ठ चुनाव पर्यवेक्षक ने खुले तौर पर सीईसी ज्ञानेश कुमार को चुनौती दे दी। कूच बिहार में तैनात इस पर्यवेक्षक का नाम अनुराग यादव है। उनके चुनाव आयुक्त से अभद्र व्यवहार के बाद उन्हें उस पद से हटा दिया गया। ईसी की पूर्ण पीठ ने इस बैठक को वर्चुअल माध्यम से बुलाया था। बैठक के दौरान कूच बिहार दक्षिण के सामान्य

पर्यवेक्षक अनुराग यादव ने सीईसी की टिप्पणियों पर आपत्ति जताई। सूत्रों के अनुसार, स्थिति तब और तनावपूर्ण हो गई जब सीईसी ज्ञानेश कुमार ने यादव से उन्हें घर लौट जाने के लिए कहा। अनुराग यादव ने पलटवार करते हुए कहा कि आप हमारे साथ इस तरह का व्यवहार नहीं कर सकते। हमने इस सेवा में 25 साल समर्पित किए हैं। आप इस तरह बात नहीं कर सकते। यादव उत्तर प्रदेश सरकार में प्रमुख सचिव रैंक के अधिकारी हैं। सूत्रों ने बताया कि इस तीखी बहस के बाद बैठक में कुछ समय के लिए सन्नाटा छा गया। बाद में अन्य मुद्दों पर चर्चा फिर से शुरू हुई। चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने तुरंत प्रभाव से अनुराग यादव को सामान्य पर्यवेक्षक के पद से हटा दिया। हालांकि, चुनाव आयुक्त कार्यालय के सूत्रों ने कहा कि यह कदम उनके 'विद्रोही रवैये' के कारण नहीं, बल्कि पेशेवर अक्षमता के चलते उठाया गया।

भीषण सड़क हादसे में तीन की मौत, दस घायल

कोलकाता। उत्तर 24 परगना जिले के बशीरहाट उपमंडल के मिनाखा थाना क्षेत्र में स्थित बसंती हाईवे पर आज एक भीषण सड़क हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि कम से कम दस अन्य यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों की हालत नाजुक बताई जा रही है। पुलिस के अनुसार यह दुर्घटना मिनाखा ग्राम पंचायत कार्यालय के सामने हुई। जानकारी के मुताबिक एक ऑटो-रिक्शा कई यात्रियों को लेकर मालंचा से कोलकाता की ओर जा रहा था। इसी दौरान कोलकाता से लौट रही एक तेज रफ्तार चारपहिया वाहन अचानक नियंत्रण खो बैठी और सीधे ऑटो से टकरा गई। आमने-सामने की इस टक्कर में ऑटो सड़क किनारे जा पलटा। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई।

मुस्लिम वोटों के लिए 1000 करोड़ का सौदा....

हुमायूं कबीर का पलटवार.. सबूत दिखाने की कही बात

नई दिल्ली। एजेंसी

पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी माहौल अचानक गरमा गया है। विवाद के केंद्र में हैं हुमायूं कबरी, जो आम जनता उन्नयन पार्टी के प्रमुख हैं। तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) ने एक वीडियो जारी कर बड़ा आरोप लगाया है कि कबीर भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर करोड़ों रुपये के सौदे में शामिल हैं और मुस्लिम वोटों को प्रभावित करने की साजिश रच रहे हैं। इस आरोप के बाद राज्य की राजनीति में तीखी बयानबाजी शुरू हो गई

है। दरअसल, टीएमसी नेता फिरहाद हकीम, अरूप बिस्वास और कुणाल घोष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक कथित वीडियो पेश किया। इस वीडियो में दावा किया गया कि हुमायूं कबीर किसी बातचीत में '1000 करोड़ रुपये' और मुस्लिम समुदाय को गुमराह करने जैसी बातें कर रहे हैं। कुणाल घोष ने यह भी आरोप लगाया कि इस कथित सौदे में प्रधानमंत्री ऑफिस (पीएमओ) तक की भूमिका हो सकती है और उन्होंने ईडी से जांच की मांग की। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी का कहना है कि भाजपा, पश्चिम बंगाल में मुस्लिम वोटों को बांटने की रणनीति पर काम कर रही है। हुमायूं कबीर ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि यह वीडियो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के जरिए बनाया गया है और पूरी तरह नकली है।

अजित जैसी जैकेट और वही अंदाज!

पार्थ ने ली राज्यसभा सांसद पद की शपथ

नई दिल्ली। महाराष्ट्र की राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत हो गई है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता और दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार के निधन के बाद, पवार परिवार और पार्टी अब नए नेतृत्व की ओर देख रही है। जहां एक तरफ पार्टी की कमान सुनेत्रा पवार मजबूती से संभाल रही हैं, वहीं दूसरी ओर आज उनके पुत्र पार्थ पवार ने आधिकारिक तौर पर देश के उच्च सदन यानी राज्यसभा के सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण की। संसद भवन के भव्य गलियारों में आज का दिन बेहद भावुक रहा। शपथ ग्रहण समारोह के दौरान

सबकी निगाहें पार्थ पवार के पहनावे पर टिकी थीं। पार्थ ने इस विशेष अवसर पर वही नेहरू जैकेट पहनी थी, जो उनके पिता अजित पवार की पहचान मानी जाती थी। राजनीतिक गलियारों में इसे केवल एक वस्त्र नहीं, बल्कि एक 'विरासत के हस्तांतरण' के रूप में देखा जा रहा है।

तालाब में डूबने से दो बालकों की मौत

जौनपुर,। मछलीशहर कोतवाली क्षेत्र में मंगलवार को तालाब में डूबने से दो बच्चों की मौत हो गई। घटना से पूरे गांव में कोहराम मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।बताते है कि पराहित गांव निवासी अरविंद का 12 वर्षीय पुत्र मोनू उर्फ सत्यम और लालबहादुर का 9 वर्षीय पुत्र उमंग बिना बताए गांव के पास स्थित तालाब में नहाने चले गए। उस समय परिवार के सदस्य खेतों में गेंहू की कटाई के काम में व्यस्त थे। परिजन शाम को जब खेतों से लौटे तो दोनों बच्चे घर पर नहीं मिले। इसके बाद उनकी तलाश शुरू की गई। काफी खोजबीन के बाद घर से करीब 500 मीटर दूर तालाब में दोनों के शव मिलने की सूचना मिली।

एलपीजी की किल्लत से मिलेगी राहत!

15,400 टन गैस लेकर लौटा ग्रीन आशा होर्मुज से कैसे निकला भारतीय जहाज ?

नई दिल्ली। मीडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच नवी मुंबई के समुद्री तट से भारत के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है। जहां रसोई गैस यानी लेकर एक भारतीय जहाज सुरक्षित पहुंच गया है। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी ने गुरुवार, 9 अप्रैल 2026 को बताया कि 15,400 टन एलपीजी लेकर आ रहा एक बड़ा जहाज नवी मुंबई के पोर्ट पर सफलतापूर्वक पहुंच चुका है। यह खबर इसलिए खास है, क्योंकि इस जहाज ने इस वक्त दुनिया के सबसे खतरनाक समुद्री रास्ते स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को पार किया है, जहां इस

समय ईरान, अमेरिका और इजरायल के बीच छिड़ी जंग की वजह से भारी तनाव बना हुआ है। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी ने जानकारी दी है कि ग्रीन आशा नाम का यह भारतीय जहाज सुरक्षित तरीके से अपनी मंजिल पर पहुंच गया है। इस जहाज को जवाहरलाल नेहरू पोर्ट के उस विशेष हिस्से (बर्थ) पर खड़ा किया गया है, जिसका संचालन भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन मिलकर करते हैं। पश्चिम एशिया में युद्ध शुरू होने के बाद से यह इस तरह का पहला जहाज है, जो इतने खतरनाक माहौल के बावजूद वहां से निकलकर सीधे इस पोर्ट पर पहुंचा है। अधिकारियों का कहना है कि यह भारत के लिए एक बड़ी जीत जैसा है क्योंकि युद्ध के कारण इस रास्ते से गुजरना बहुत मुश्किल हो गया था। इस पूरे मिशन की सबसे अच्छी बात यह रही कि जहाज पर मौजूद चालक दल के सभी सदस्य पूरी तरह सुरक्षित हैं। जहाज में लदी 15,400 टन एलपीजी और खुद जहाज को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा है।

तीनों राज्यों में रिकार्ड तोड़ मतदान हुआ

पुडुचेरी में टूटे वोटिंग के सारे रिकॉर्ड 86 प्रतिशत से ज्यादा मतदान, केरल और असम में भी जबरदस्त उत्साह.....

असम/ एजेंसी

असम, केरल और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान में जोरदार रुझान देखा गया। शाम 5 बजे तक प्राप्त आंकड़ों से तीनों राज्यों में मजबूत मतदाता भागीदारी का संकेत मिला है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, पुडुचेरी में सबसे अधिक 86.92 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया। इसके बाद असम में 84.42 प्रतिशत और केरल में 75.01 प्रतिशत के साथ मतदान संपन्न हुआ। असम में सभी 126 विधानसभा सीटों पर एक चरण में मतदान हुआ। शाम 5 बजे तक अनुमानित 84.42 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया, जो 2021 के विधानसभा चुनावों के 82.04 प्रतिशत से अधिक है। प्रदेश में कड़ी टक्कर देखी जा रही है। भाजपा के नेतृत्व वाला एनडीए लगातार तीसरी बार सत्ता में बने रहने की कोशिश कर रहा है, जबकि कांग्रेस एक दशक बाद सत्ता में वापसी का लक्ष्य लेकर चुनाव लड़ रही है। असम के दलगांव विधानसभा क्षेत्र में सबसे अधिक 94.57 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया, जबकि अमरी क्षेत्र में सबसे कम 70.40 प्रतिशत मतदान रहा। इस चुनाव में कुल 722 उम्मीदवार मैदान में हैं। राज्य के 35 जिलों में फैले 31,490 मतदान केंद्रों पर सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान चला। केरल में सभी 140

विधानसभा सीटों के लिए मतदान शाम 6 बजे समाप्त हुआ। हालांकि, कई मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लंबी कतारें लगी रहीं। निर्धारित समय के बाद भी कतार में खड़े मतदाताओं को टोकन जारी कर उन्हें वोट डालने की अनुमति दी गई। शाम 5 बजे तक केरल में 75.01 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया, जो 2021 के 74.06 प्रतिशत से थोड़ा अधिक है। सभी मतदाताओं के वोट डालने के बाद अंतिम मतदान प्रतिशत जारी किया जाएगा। वहीं, पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश में 30 विधानसभा क्षेत्रों के लिए मतदान शाम 6 बजे समाप्त हुआ। समय सीमा से पहले पहुंचे मतदाताओं को कतार में इंतजार कर वोट डालने की अनुमति दी गई। शुरुआती अनुमानों के मुताबिक यहां मतदान प्रतिशत 86 प्रतिशत से अधिक रहा। एनडीए पुडुचेरी में सत्ता बरकरार रखने का प्रयास कर रहा है, जबकि कांग्रेस के नेतृत्व वाला विपक्षी गठबंधन स्थानीय स्वायत्तता और प्रशासनिक मुद्दों को लेकर एआईएनआरसी के नेतृत्व वाले गठबंधन को सत्ता से बाहर करने की कोशिश में जुटा है।

अतीक अहमद जैसा हाल होगा

अविमुक्तेश्वरानंद को जान से मारने की धमकी मिली

नई दिल्ली। ज्योतिष्पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को जान से मारने की धमकी मिलने का मामला सामने आया है। उन्हें कुख्यात गैंगस्टर अतीक अहमद की तरह मारने की धमकी दी गई है, जिससे उनके अनुयायियों में हड़कंप मच गया है।उनके मीडिया प्रभारी संजय पांडेय के अनुसार, ज्योतिर्मठ के आधिकारिक नंबर पर धमकी भरे मैसेज और ऑडियो भेजे गए हैं। यह पहली बार नहीं है, इससे पहले भी उन्हें जान से मारने की धमकियां मिल चुकी हैं। बताया गया कि शंकराचार्य 'गौ माता-राष्ट्रमाता' अभियान चला रहे हैं, जिसका उद्देश्य देश में गौहत्या पर

रोक लगाना है। इसी के तहत 3 मई से उत्तर प्रदेश के हर विधानसभा क्षेत्र में उनकी 'गविष्ठी यात्रा' प्रस्तावित है। इस दौरान वे लोगों को गौ रक्षा के लिए जागरूक करेंगे और हर क्षेत्र में 'रामा गौ धाम' बनाने का संदेश देंगे। संजय पांडेय का कहना है कि इस अभियान से कुछ विरोधी समूह नाराज हैं।

नगर पंचायत बेरला मे 1 करोड़ 21 लाख रूपये विकास कार्यों का हुआ भूमिपूजन

बेमेतरा। नगर पंचायत बेरला, में विभिन्न मदों से स्वीकृत विकास कार्यों के भूमिपूजन कार्यक्रम का आयोजन नगर पंचायत द्वारा किया गया, जिसमें क्षेत्रीय विधायक दीपेश साहू मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित हुए। कार्यक्रम की अध्यक्षता नगर पंचायत अध्यक्ष विशाल राज देशलहरा ने किया। कार्यक्रम की शुरुवात सर्वप्रथम विधायक दीपेश साहू ने शीतला माता मंदिर मे पूजा कर आशीर्वाद प्राप्त कर क्षेत्रवासियों के शुभकामनायें के साथ की। तत्पश्चात विधि-विधान के साथ पूजा-अर्चना कर कुल 1 करोड़ 21 लाख रुपये के विभिन्न विकास कार्यों का भूमिपूजन किया गया। जिसके अंतर्गत 15 प्रमुख कार्यों के लिए 1 करोड़ 21 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। इन कार्यों में वार्ड क्रमांक 08 में शीतला तालाब महतारी घाट निर्माण, वार्ड क्रमांक 07 नवा तरिया महतारी घाट निर्माण, वार्ड क्रमांक 03/13 खरगा तालाब महतारी घाट निर्माण, वार्ड क्रमांक 03 में शनि मंदिर के पास मुक्तिधाम प्रतिक्षालय निर्माण, वार्ड क्रमांक 10 मड़ई मैदान कृष्णा मंदिर के पास हाट बाजार निर्माण, वार्ड क्रमांक 13 में सीसी रोड टॉप लेयर कार्य, वार्ड क्रमांक 7/8 सतनामी मोहल्ला में सीसी रोड टॉप लेयर, वार्ड क्रमांक 07 नवा तरिया से शिव मंदिर तक सीसी रोड निर्माण, वार्ड क्रमांक 10 में शिव मंदिर एवं कृष्ण मंदिर के आसपास सीसी रोड निर्माण, वार्ड क्रमांक 06 में विभिन्न स्थलों पर सीसी रोड निर्माण तथा वार्ड क्रमांक 09 में जय स्तंभ के पास हाईमास्क इसके अलावा नगर पंचायत के 4 विभिन्न स्थलों पर हाई मास्क लाइट की स्थापना जैसे महत्वपूर्ण कार्य शामिल हैं। इस अवसर पर विधायक दीपेश साहू ने नगर पंचायत प्रतिनिधियों एवं पार्षदों की मांग पर शीतला मंदिर में ज्योति कक्ष एवं अतिरिक्त कक्षा निर्माण हेतु 10 लाख रुपये की घोषणा की, साथ ही एक सुलभ शौचालय निर्माण की भी घोषणा की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक दीपेश साहू ने कहा कि बेरला नगर पंचायत क्षेत्र के समग्र विकास के लिए वे निरंतर प्रतिबद्ध हैं और शासन की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना उनकी प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि अधोसंरचना के इन कार्यों से नगर के विभिन्न वार्डों में सड़क, तालाब, घाट, प्रकाश व्यवस्था एवं सार्वजनिक सुविधाओं का विस्तार होगा, जिससे आमजन को सीधा लाभ मिलेगा और क्षेत्र के विकास को नई गति मिलेगी। विधायक साहू ने कहा कि प्रदेश की सरकार और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में ग्रामीण एवं शहरी विकास को प्राथमिकता दी जा रही है, और बेरला भी विकास के इस क्रम में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने सभी जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों एवं नगरवासियों से अपील की कि वे विकास कार्यों में सहयोग करें तथा योजनाओं का सही उपयोग सुनिश्चित करें। अंत में विधायक साहू ने भरोसा दिलाया कि भविष्य में भी क्षेत्र के विकास के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे और किसी भी प्रकार की कमी नहीं आने दी जाएगी।

स्वच्छता को लेकर विशेष अपील

अपने संबोधन के अंत में विधायक दीपेश साहू ने समस्त बेरला नगर पंचायत वासियों से स्वच्छता बनाए रखने की विशेष अपील की। उन्होंने कहा कि हमें अपने गांव, मोहल्ले और घर-परिवार के आसपास स्वच्छता बनाए रखने की आदत विकसित करनी होगी। उन्होंने कहा, जब हमारा आसपास का वातावरण स्वच्छ और सुंदर होगा, तो हमारा मन भी सकारात्मक और स्वच्छ रहेगा, जिससे हम एक अच्छे समाज और राष्ट्र के निर्माण में योगदान दे सकेंगे। विधायक ने अपील करते हुए कहा कि गली-मोहल्लों, सड़कों, नालों, तालाबों और नदियों के आसपास सफाई रखें, कचरा इधर-उधर न फैलाएं और पॉलीथिन का उपयोग कर उसे सड़क किनारे न फेंकें। उन्होंने सभी नागरिकों से स्वच्छता अभियान में सक्रिय भागीदारी निभाने का आह्वान किया। इस दौरान उन्होंने क सराहनीय पहल की घोषणा भी की उन्होंने कहा की जो वार्ड सबसे स्वच्छता रहेगा मे सबसे आगे रहेगा उसको इनाम सहित विकाश कार्यों की सौगात उनकी वार्डो सबसे ज्यादा दी जाएगी। कार्यक्रम मे विधायक प्रतिनिधि अमृत लाल महेश्वरी नगर पंचायत उपाध्यक्ष संतोष साहू मण्डल अध्यक्ष डोमेन्द्र राजपूत राजू साहू सभापति शिवझड़ी सिन्हा मानक चतुर्वेदी यतिद्ध द्विवेदी कन्हैया सेन बलराम साहू बलराम सिवारे उमा अनंत बलराम यादव मधुरा साहू पोखराज सोनी राजेश दुबे जयप्रकाश बघेल लेखराम साहू खेमराज साहू अजित कुमार वर्मा सीएमओ सचिन गुप्ता सब इंजिनियर शशि प्रताप सहित नगर पंचायत के समस्त जनप्रतिनिधि गण अधिकारी कर्मचारी नगरवासी उपस्थित रहे।

मुख्य नगर पालिका अधिकारी सीमा बख्शी ने किया बस स्टैंड परिसर एवं शौचालय का निरीक्षण

दल्लीराजहरा। मुख्य नगर पालिका अधिकारी सीमा बख्शी द्वारा स्वच्छता बनाए रखने के लिए नगर पालिका क्षेत्र अंतर्गत वार्ड क्रमांक 24 में बस स्टैंड परिसर एवं शौचालय का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान शौचालय में सफाई, पानी की आपूर्ति, बिजली और प्रकाश व्यवस्था जायजा लिया। शौचालय में नियमित रखरखाव सुनिश्चित करने, शौचालय परिसर को साफ रखने एवं कीटनाशक उपयोग करने के निर्देश दिए। इस दौरान मुख्य नगर पालिका अधिकारी सीमा बख्शी ने तत्काल संबंधित विभाग को निर्देशित करते हुए नये दरवाजे, टूटे हुए सीटों को बदला गया एवं नलों में टोटी लगाई गई। रैन बसेरा के ऊपर पानी टंकी को साफ करवाया गया जिससे वार्ड वासियों एवं यात्रियों को शुद्ध पानी की प्राप्ति हो एवं पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कहा गया। निरीक्षण के दौरान राजस्व प्रभारी बुद्धिमान सिंह, स्वच्छता प्रभारी सतीश चंद्राकर, भंडार प्रभारी प. कज चंद्राकर उपस्थित रहे।

उत्कर्ष योजना के अंतर्गत आवेदन आमंत्रित

दल्लीराजहरा। मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति तथा जनजाति विद्यार्थी उत्कर्ष योजना 2026-27 के क्रियान्वयन अंतर्गत उत्कृष्ट आवासीय शिक्षण संस्थानों के इम्पेनलमेंट हेतु 'रुचि की अभिव्यक्ति' आमंत्रित की गई है। आदिवासी विकास विभाग के सहायक आयुक्त ने बताया कि मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति तथा जनजाति विद्यार्थी उत्कर्ष योजना अंतर्गत अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति वर्ग के ग्रामीण प्रतिभावान विद्यार्थियों को गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना, नई सोच के साथ बेहतर कैरियर चयन का अवसर प्रदान करते हुए प्रतिस्पर्धी बनाना तथा बहुमुखी व्यक्तित्व विकास के लिए अवसर प्रदान करना है। इस योजना अंतर्गत विद्यार्थी को कक्षा 6वीं से 12वीं तक छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित उत्कृष्ट आवासीय विद्यालय को शिक्षण प्रदान निर्धारित मानक शुल्क की प्रतिपूर्ति किया जाएगा। उन्होंने बताया कि जिले से संबंधित समस्त प्रस्ताव, सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग कार्यालय में 23 अप्रैल को शाम 05 बजे तक जमा करना अनिवार्य है।

10 अप्रैल से खुलेगा मानव रहित समपार फाटक अंडर ब्रिज

दल्लीराजहरा। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे रायपुर रेल मंडल के दुर्ग दल्लीराजहरा सेक्शन में मानव रहित समपार फाटक डी.डी.- 39 किमी.- 910/3-4 सिकोसा-पिनकापार गेट के पास में रोड अंडर ब्रिज निर्माण का कार्य पूर्ण हो गया है। इसे आम जनता के लिए 10 अप्रैल (सुबह 6:00 बजे) से रोड अंडर ब्रिज खोल दिया जायेगा एवं समपार फाटक (लेवल क्रासिंग) डी.डी.- 39 को स्थायी रूप से बंद कर दिया जाएगा । इस संबंध में स्थानीय प्रशासन और रेल प्रशासन के मध्य सारी औपचारिकता पूर्ण कर ली गई है। रोड अंडर ब्रिज रेलवे और सड़क-दोनों के लिए सुरक्षित, तेज और आधुनिक समाधान है, जो आम जनता की सुविधा और क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। रोड अंडर ब्रिज बनने से रेलवे फाटक बंद होने की समस्या समाप्त हो जाती है, जिससे सड़क यातायात बिना रुके चलता रहता है। फाटक पर लंबा इंतजार नहीं करना पड़ता, जिससे यात्रियों और वाहन चालकों का समय बचता है। फाटक पार करते समय होने वाली दुर्घटनाओं की संभावना पूरी तरह खत्म हो जाती है। बार-बार फाटक बंद/खोलने की आवश्यकता नहीं होने से ट्रेनों का संचालन अधिक संरक्षा के साथ और समयबद्ध होता है।

शुद्ध के लिए युद्ध : विश्व स्वास्थ्य दिवस पर भ्रामक फूड विज्ञापनों के खिलाफ उठी कड़ी आवाज

बेमेतरा। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल के अवसर पर देश में पैकेज्ड फूड और पेय पदार्थों की गुणवत्ता को लेकर गंभीर बहस तेज हो गई है, शुद्ध के लिए युद्ध का आह्वान करते हुए भाजपा महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष प्रज्ञा निर्वाणी ने जूस और आइसक्रीम के नाम पर बेचे जा रहे भ्रामक उत्पादों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है, इस संबंध में जिला भाजपा महिला मोर्चा अध्यक्ष प्रज्ञा निर्वाणी के साथ खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग को कॉलेज की छात्रों ने पत्र लिखकर जनस्वास्थ्य की रक्षा हेतु तत्काल ठोस कदम उठाने की अपील की है। प्रज्ञा निर्वाणी ने कहा कि आज बाजार में फ्रूट जूस के नाम पर ऐसे पेय बेचे जा रहे हैं जिनमें वास्तविक फल की मात्रा कई मामलों में मात्र 10 से 20 प्रतिशत तक सीमित है, जबकि शेष हिस्सा शुगर, कृत्रिम फ्लेवर और प्रिजर्वेटिव्स से भरा होता है,एक सामान्य 200 मिलीलीटर पैक में 20 से 25 ग्राम तक शुगर पाई जाती है, जो एक व्यक्ति के पूरे दिन की सुरक्षित सीमा के बराबर है। इसी प्रकार आइसक्रीम के नाम पर बिकने वाले कई उत्पाद वास्तव में फ्रोजन डेजर्ट हैं, जिनमें दूध के स्थान पर वनस्पति तेल और कृत्रिम तत्वों का उपयोग किया जाता है, लेकिन प्रस्तुतीकरण ऐसा होता है कि आम उपभोक्ता भ्रमित हो जाता है। उन्होंने इसे केवल व्यापारिक अनियमितता नहीं, बल्कि जनता के स्वास्थ्य के साथ गंभीर धोखा बताया,इस संदर्भ में उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ही देश की एकमात्र ऐसी राजनीतिक शक्ति है जो राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ कार्य करती हुए जनता को जनार्दन मानती है, और इसी भावना के तहत आम नागरिकों के स्वास्थ्य, अधिकार और सुरक्षा के लिए संघर्ष करना अपना कर्तव्य समझती है। चिकित्सा विशेषज्ञ डॉ भावना चंद्राकर का कहना है कि अत्यधिक शुगर और प्रोसेस्ड फूड का सेवन देश में तेजी से बढ़ रही बीमारियों का प्रमुख कारण बन रहा है, भारत में 10 करोड़ से अधिक लोग मधुमेह से प्रभावित हैं, जबकि हर पांच में एक व्यक्ति मोटापे की समस्या से जूझ रहा है,हृदय रोग और फैटी लिवर जैसी बीमारियां भी तेजी से बढ़ रही हैं, विशेषकर बच्चों और युवाओं में इसका खतरा अधिक देखा जा रहा है। विश्व स्वास्थ्य दिवस के संदर्भ में प्रज्ञा निर्वाणी ने विकसित देशों का उदाहरण देते हुए कहा कि ब्रिटेन, अमेरिका, चिली और यूरोपीय देशों में ऐसे उत्पादों पर कड़े नियम लागू हैं, जहां पैकेजिंग पर स्पष्ट चेतावनी, भ्रामक दावों पर प्रतिबंध और कंपनियों पर भारी दंड का प्रावधान है, उन्होंने कहा कि भारत में भी उपभोक्ताओं को भ्रम से बचाने के लिए इसी प्रकार की सख्त व्यवस्था लागू की जानी चाहिए। उन्होंने अपने पत्र में मांग की है कि जूस और आइसक्रीम शब्दों के उपयोग के लिए स्पष्ट और सख्त मानक तय किए जाएं, फ्रोजन डेजर्ट और शुगर युक्त पेय पदार्थों को स्पष्ट रूप से चिन्हित किया जाए, तथा पैकेजिंग पर अनिवार्य रूप से स्वास्थ्य चेतावनी अंकित की जाए। साथ ही भ्रामक विज्ञापन करने वाली कंपनियों के खिलाफ कड़ी दंडात्मक कार्रवाई करते हुए भारी जुर्माना एवं लाइसेंस निरस्तीकरण जैसे कदम उठाए जाएं। प्रज्ञा निर्वाणी ने कहा कि शुद्ध के लिए युद्ध को जनआंदोलन का रूप दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह केवल एक अभियान नहीं, बल्कि देश की जनता के स्वास्थ्य और भविष्य की रक्षा का संकल्प है।

अब दलहन में आत्मनिर्भर बनेगा धमतरी, लोहरसी से हुई मजबूत शुरुआत

धमतरी। दलहन आत्मनिर्भरता मिशन अंतर्गत धमतरी जिले के ग्राम लोहरसी में किसानों को उड़द बीज का वितरण एवं तकनीकी मार्गदर्शन दिया गया। धमतरी में किसान धान के बदले रबि में फसल चक्र परिवर्तन अंतर्गत दलहन तिलहन की फसल अपना रहे है। इसके अलावा मखाना और औषधि की खेती की ओर झुकाव होने लगा है। वे मखाना और औषधि की खेती भी कर रहे है। इसके लिए कृषि विभाग के साथ जिला प्रशासन ने किसानों को प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। दालें सिर्फ एक कृषि उत्पाद नहीं हैं। वे भारत की पोषण सुरक्षा, मृदा स्वास्थ्य और ग्रामीण आजीविका का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। दुनिया में दालों के सबसे बड़े उत्पादक, उपभोक्ता और आयातक के रूप में, भारत की नीतियां लगातार इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में उत्पादकता और स्थिरता बढ़ाने पर केंद्रित रही हैं। बढ़ती आय और संतुलित पोषण के प्रति बढ़ती जागरूकता के साथ, दालों की मांग लगातार बढ़ रही है, जिससे घरेलू उत्पादन बढ़ाने के अवसर पैदा हो रहे हैं। दालों का आर्थिक और व्यापारिक महत्व तो है ही, साथ ही ये पोषक तत्वों का भी भंडार हैं। राष्ट्रीय पोषण संस्थान के अनुसार, भारतीय आहार में कुल प्रोटीन की मात्रा में इनका योगदान लगभग 20-25 प्रतिशत है। हालांकि, प्रति व्यक्ति दालों की खपत अनुशंसित 85 ग्राम प्रतिदिन से कम है, जिसके कारण देश भर में प्रोटीन-ऊर्जा कुपोषण की समस्या बढ़ रही है। इसलिए घरेलू उत्पादन बढ़ाना न केवल आर्थिक आवश्यकता है, बल्कि जन स्वास्थ्य में सुधार की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम है। मालूम हो कि इस दोहरे महत्व को पहचानते हुए, भारत सरकार ने दलहन क्षेत्र को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया है। 11 अक्टूबर 2025 को नई दिल्ली स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान आईएआरआई में एक विशेष कृषि कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11,440 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ दलहन आत्मनिर्भरता मिशन दलहन आत्मनिर्भरता मिशन का शुभारंभ किया था। इस कार्यक्रम के दौरान, प्रधानमंत्री ने दलहन की खेती में लगे किसानों से बातचीत भी थी और कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में मूल्य श्रृंखला आधारित विकास को बढ़ावा देने के महत्व पर प्रकाश डाला था। उन्होंने इस बात पर बल दिया गया कि इस मिशन का उद्देश्य न केवल दलहन उत्पादन बढ़ाना है, बल्कि एक सतत और सशक्त भविष्य का निर्माण करना भी है। यह मिशन पोषण सुरक्षा और आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

बेटी को उपहार ग्रुप द्वारा हेमलता के विवाह की रस्में संपन्न

धमतरी। सामाजिक संवेदनशीलता और सहभागिता का एक उत्कृष्ट उदाहरण सामने आया, जब बेटी को उपहार ग्रुप धमतरी के माध्यम से लालबगीचा वार्ड की बेटी हेमलता के विवाह पूर्व पारंपरिक झाला वारना एवं खोल भरने की रस्म सादगी और गरिमा के साथ संपन्न की गई। इस अवसर पर नवजीवन की मंगलकामनाओं के साथ बेटी को उपहार प्रदान कर आशीर्वाद दिया गया। कार्यक्रम में सदस्य नेहा गोयल ने घरवा रस्म निभाते हुए बेटी को नोज पिन एवं सुहाग सामग्री भेंट की तथा उसके चरण स्पर्श कर स्नेह और आशीष प्रदान किया। इस भावपूर्ण क्षण ने पूरे वातावरण को आत्मीय बना दिया। उल्लेखनीय है कि लगभग चार वर्ष पूर्व हेमलता की माता के आकस्मिक निधन के पश्चात उनके पिता श्रवण सेन को अपनी तीसरी छोटी पुत्री के पालन.पोषण एवं शिक्षा में अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ा। ऐसे में जब हेमलता का विवाह एक अच्छे परिवार में तय हुआ तो एक ओर खुशी थी, वहीं दूसरी ओर उसे सुखपूर्वक विदा करने की चिंता भी स्वाभाविक रूप से बनी हुई थी। परिजनों द्वारा परिस्थिति से अवगत कराए जाने पर बेटी को उपहार ग्रुप धमतरी के माध्यम से सहयोग की पहल की गई जिसके अंतर्गत विवाह हेतु आवश्यक सामग्री, पोशाक एवं उपहारों की व्यवस्था की गई। इस अवसर पर रसीला बेन दोशी, प्रभा रावत, सूर्या लुंकड़, रीता लुंकड़, कविता राठी, नेहा गोयल एवं डॉ सरिता दोशी ने पारंपरिक रस्मों का निर्वहन करते हुए बेटी को आशीर्वाद प्रदान किया। कार्यक्रम में हेमलता की बुआ, कजिन एवं अन्य परिजन भी उपस्थित रहे। उन्होंने भावुक होकर प्राप्त सहयोग के प्रति आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर ग्रुप की संरक्षक प्रभा रावत ने बताया कि संपर्क करने वाले परिवार की परिस्थितियों को समझते हुए, उनकी आवश्यकता के अनुरूप विवाह के लिए आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाता है। साथ ही, एक सादगीपूर्ण कार्यक्रम के माध्यम से बेटी को शगुन स्वरूप सामग्री भेंट कर शुभकामनाएं दी जाती हैं। संयोजक डॉ सरिता दोशी ने बताया बेटी को उपहार ग्रुप के माध्यम से वर्ष 2016 से प्रारंभ इस पहल के अंतर्गत यह 20वीं बेटी है, जिसके विवाह पूर्व यह परंपरा निभाई गई।

मिशन गांव चलो अभियान के तहत बूथ कमेटियों का गठन

सरायपाली। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर मिशन गाँव चलो अभियान के अंतर्गत संगठन को जमीनी स्तर तक सशक्त एवं सक्रिय बनाने हेतु व्यापक स्तर पर पंचायत एवं बूथ कमेटियों के गठन की प्रक्रिया निरंतर जारी है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मार्गदर्शन एवं जिलाध्यक्ष द्वारकाधीश यादव तथा विधायक चातुरी नंद के निर्देशन में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ग्रामीण के अध्यक्ष तेजराम पटेल के नेतृत्व में कांग्रेस की टीम गांव-गांव पहुंचकर संगठन को मजबूती प्रदान करने और कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारियां सौंपने का कार्य कर रही है। इसी क्रम में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी सरायपाली ग्रामीण के अंतर्गत विभिन्न ग्राम पंचायतों में संगठन विस्तार का महत्वपूर्ण कार्य संपन्न किया गया। अभियान के तहत ग्राम कुटेला, जोगनीपाली, पंधी, बिलाईगढ़, माधोपाली सहित जंगलबेड़ा, राजाडीह, भालुकोना, पजरापाली, गिधामुड़ा, बेलडीह, सरायपाली, लमकेनी, तोषगांव, गोहरापाली, अर्तला, पंडापारा एवं तोरेसिंघा में पंचायत कमेटियों एवं बूथ कमेटियों का गठन किया गया। इस दौरान कांग्रेस पदाधिकारियों ने ग्रामीणों से संवाद स्थापित करते हुए संगठन की नीतियों एवं विचारधारा से अवगत कराया तथा अधिक से अधिक लोगों को कांग्रेस संगठन से जोड़ने का आह्वान किया। कार्यक्रम में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी सरायपाली ग्रामीण के प्रमुख पदाधिकारी विजय नायक।

महापौर ने किया ग्राम रत्नाबांधा में विकास कार्यों का भव्य भूमिपूजन

महापौर रामू रोहरा के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ कार्यक्रम, कीर्तन मीनपाल के प्रयासों से संवर रहा ग्राम

धमतरी। रत्नाबांधा के शासकीय स्कूल परिसर में विभिन्न विकास कार्यों का भूमिपूजन कार्यक्रम पूरे हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि धमतरी नगर निगम के महापौर रामू रोहरा थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता एवं संचालन जनपद पंचायत धमतरी के सदस्य कीर्तन मीनपाल द्वारा किया गया। इस भव्य भूमिपूजन समारोह के साथ ही गांव में कुल 20 लाख रुपये की लागत से होने वाले महत्वपूर्ण निर्माण कार्यों का श्री गणेश हो गया है। कार्यक्रम के दौरान मुख्य रूप से दो प्रमुख विकास कार्यों की आधारशिला रखी गई। शासकीय स्कूल परिसर में 10 लाख रुपये की लागत से टीन शेड निर्माण कार्य एवं सड़क निर्माण राजेश मीनपाल के घर से पीजी कॉलेज रोड की ओर 10 लाख रुपये की लागत से सीसी रोड निर्माण कार्य शामिल है। मुख्य अतिथि रामू रोहरा महापौर धमतरी नगर निगम ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और हमारी प्राथमिकता आम जनता तक बुनियादी सुविधाएं पहुंचाना है। ग्राम रत्नाबांधा में शिक्षा और आवागमन की सुविधा को बेहतर बनाने के लिए आज जिन 20 लाख रुपये के कार्यों का भूमिपूजन हुआ है, वह मील का पत्थर साबित होगा। स्कूल में टीन शेड बनने से बच्चों को सुविधा होगी और सीसी रोड से ग्रामीणों का आवागमन सुगम होगा। हम क्षेत्र के चहुंमुखी विकास के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। कीर्तन मीनपाल सदस्य जनपद पंचायत धमतरी ने कार्यक्रम में अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा यह आप सभी ग्रामवासियों का आशीर्वाद ही है कि आज हमारा ग्राम रत्नाबांधा निरंतर संवर रहा है। चुनाव के समय जो संकल्प हमने लिए थे, उन्हें आज धरातल पर उतारने का काम किया जा रहा है। शिक्षा के मंदिर का विकास और गांव की सड़कों का सुदृढ़ीकरण हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। जनता के विश्वास और सहयोग से विकास की यह अविरल धारा आगे भी इसी तरह बहती रहेगी। फकीरचंद वर्मा सरपंच ग्राम पंचायत रत्नाबांधा की ओर से खुशी जाहिर करते हुए सरपंच ने कहा पूरे ग्राम रत्नाबांधा के लिए हर्ष का विषय है। एक साथ 20 लाख रुपये के विकास कार्यों की सौगात मिलने से गांव में विकास को एक नई गति मिलेगी। आभार जताते हुए कहा आज हमारे ग्राम पंचायत की एक बहुप्रतीक्षित मांग पूरी हो रही है। मैं इस सौगात के लिए सभी अतिथियों और शासन-प्रशासन का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। ग्राम पंचायत अपने नागरिकों की हर छोटी.बड़ी समस्या के समाधान और गांव के निरंतर विकास के लिए आगे भी इसी तरह एकजुट होकर कार्य करती रहेगी।

इस भूमिपूजन कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में भाजपा आमदी मंडल अध्यक्ष विनय जैन और धमतरी के समाजसेवी दीपक ठाकुर ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई इनके साथ ही पूर्व सरपंच रामभागवत मीनपाल और गांव के वरिष्ठ नागरिक रामसिंग मंडावी, दिलीप मीनपाल, जोहन पाल और नाथोराम साहू भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। समारोह के सफल आयोजन में उपसरपंच दादू लाल यदु, सचिव दधिची अग्रवाल, रोजगार सहायक सुनिता मीनपाल सहित पंचायत के सभी सम्मानित पंचगण अंजली मीनपाल, बिसाली ध्रुव, कु. तेजेश्वरी मीनपाल, भूषण वर्मा, देवकुंवर साहू, कांति सेन, गोदावरी अग्रवाल, सरोज साहू, सविता ध्रुव, सविता यादव, दुर्गा नेताम, स्कूल के शिक्षक शिक्षिका वेणुका देवांगन प्राचार्य, ज्ञानेश्वर सिन्हा, मंजू गोस्वामी, उषा किरण गजपाल, रानी मीनपाल, शाला विकास समिति के अध्यक्ष डोमन साहू, तेजनारायण मीनपाल, ग्रामीण जन में शिवरानी खापर्डे, अमरनाथ साहू, जितेंद्र तिवारी, गोपाल साहू, लीला बाई सेन, सीमंत साहू, ढाल सिंह साहू, आरती पांडेय, दामिनी साहू, हेमलता टंडन, तमिन भाई, विनय पदमवार, पदम साहू एवं सभी सदस्यों की अहम भूमिका रही कार्यक्रम के अंत में समस्त ग्रामवासी एवं ग्राम पंचायत रत्नाबांधा की ओर से आभार व्यक्त किया गया।

संक्षिप्त समाचार

गुढियारी में बिजली कटौती के खिलाफकांग्रेस का घेराव

रायपुर। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने गुढियारी क्षेत्र में लगातार हो रही बिजली कटौती और सहायता केंद्र में अनियमितताओं के विरोध में बिजली विभाग कार्यालय का घेराव किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने विभाग और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर अपना विरोध दर्ज कराया।यह घेराव प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री सुबोध हरितवाल के नेतृत्व में किया गया, जिसमें सैकड़ों कार्यकर्ता और स्थानीय लोग शामिल हुए। सुबोध हरितवाल ने अधिकारियों को बाहर बुलाकर धूप में ही चर्चा की और कहा कि आम जनता भीषण गर्मी में परेशान है, इसलिए अधिकारियों को भी जमीनी हकीकत समझनी चाहिए।प्रदर्शन के दौरान आरोप लगाया गया कि गुढियारी क्षेत्र में पिछले 5 दिनों से बिना सूचना के रात में बिजली गुल हो रही है और सुबह तक बहाल होने का कोई निश्चित समय नहीं रहता। साथ ही, बिजली विभाग के सहायता केंद्र में कॉल रिसीव नहीं होने या फोन काट देने की शिकायतें भी सामने आई हैं, जिससे आमजन को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ये हैं प्रमुख मांगेंरातभर हो रही बिजली कटौती तत्काल बंद की जाएलाइनमैन की पर्याप्त व्यवस्था की जाएफ्यूज और डीओ बदलने की प्रक्रिया में तेजी लाई जाएओवरलोड के कारण खराब हो रहे ट्रांसफॉर्मरों की संख्या बढ़ाई जाएसहायता केंद्र में कॉल रिसीव न करने वाले ठेकेदार पर कार्रवाई की जाएअधिकारियों ने दिया आश्वासनमामले में विभाग के अधिकारी महेश ठाकुर और रामकुमार साहू ने प्रदर्शनकारियों को आश्वस्त किया कि जल्द ही बिजली कटौती की समस्या का समाधान किया जाएगा। साथ ही सहायता केंद्र के ठेकेदार पर कार्रवाई करने की बात भी कही गई।प्रदर्शन के दौरान पूर्व महापौर एजाज ढेबर, ब्लॉक अध्यक्ष सुधा सरोज, किशन बाजारी, सुंदर जोगी, रमाकांत शर्मा, अमित काचलवार सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे।

फर्जी एमबीबीएस डिग्री पर इलाज कर रहा युवक गिरफ्तार किए....

रायपुर। रायपुर पुलिस ने फर्जी एमबीबीएस डिग्री के आधार पर मेडिकल प्रैक्टिस कर रहे युवक अंकित तिवारी को गिरफ्तार किया है। आरोपी दुर्ग-भिलाई क्षेत्र में खुद को डॉक्टर बताकर मरीजों का इलाज कर रहा था। मामले में सिविल लाइन थाना में एफ्आईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।जांच के दौरान बड़ा खुलासा हुआ है कि दिल्ली में सक्रिय एक गिरोह फर्जी डिग्री तैयार कर युवकों को उपलब्ध करा रहा था। यह गैंग डी. वाई. पाटिल विद्यापीठ, पुणे के नाम से नकली एमबीबीएस डिग्री बनाकर बेचता था। पुलिस ने इस गिरोह के सरगना साक्षी सिंह को दो दिन की रिमांड पर लिया है, जिससे पूछताछ जारी है।पुलिस के मुताबिक इस मामले में जुड़े अन्य चार आरोपी—भुनेश्वर बंजारे, नरेश मनहर, हीरा दिवाकर और राकेश रात्रे—पहले से ही रायपुर जेल में बंद हैं। इन आरोपियों के जरिए कई लोगों को फर्जी डिग्री दिलाई गई, जो अलग-अलग जगहों पर मेडिकल प्रैक्टिस कर रहे थे।पुलिस ने आरोपी के पास से फर्जी डिग्री से जुड़े दस्तावेज जब्त कर लिए हैं। आरोपी अंकित तिवारी ने पूछताछ में अपना जुर्म कबूल कर लिया है। अब पुलिस उसके नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों तक पहुंचने का प्रयास कर रही है।पुलिस अधिकारियो का कहना है कि फर्जी डिग्री के आधार पर मेडिकल प्रैक्टिस करना गंभीर अपराध है और इससे आम लोगों के स्वास्थ्य पर बड़ा खतरा पैदा होता है। मामले में डिजिटल साक्ष्य और आरटीआई के माध्यम से भी जांच की जा रही है।पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि यदि कहीं भी फर्जी डॉक्टर या संदिग्ध मेडिकल प्रैक्टिस की जानकारी मिले, तो तुरंत पुलिस को सूचित करें। इस मामले में आगे की कार्रवाई कोर्ट के निर्देशानुसार की जाएगी।

अवैध शराब घोटाला : कुम्हारी डिस्टलरी से 3 और वाहन जब्त, जांच तेज

रायपुर। रायपुर में अवैध शराब घोटाले के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पुलिस और संबंधित अधिकारियों ने कुम्हारी (दुर्ग) स्थित डिस्टलरी से 3 और वाहनों को जब्त किया है। इससे पहले इस मामले में 16 वाहन पहले ही जब्त किए जा चुके हैं, जिससे पूरे नेटवर्क के संगठित होने के संकेत मिले हैं।जांच में सामने आया है कि अवैध शराब के परिवहन के लिए भरोसेमंद लोगों का उपयोग किया जाता था। डिस्टलरी से शराब उठाकर उसे शासकीय दुकानों तक पहुंचाया जाता था, जिससे पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े हो रहे हैं।अधिकारियों के अनुसार, जब्त किए गए वाहनों से बड़े पैमाने पर शराब परिवहन के प्रमाण मिले हैं। पुलिस को डिजिटल और भौतिक दोनों तरह के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जिनके आधार पर पूरे नेटवर्क की कड़ियों को जोड़ा जा रहा है।जांच के दौरान वाहन ट्रैकिंग, मोबाइल लोकेशन और अन्य डिजिटल रिकॉर्ड भी खंगाले जा रहे हैं। इसके आधार पर कई और संदिग्ध वाहनों की पहचान कर निगरानी शुरू कर दी गई है।पुलिस का कहना है कि यह घोटाला संगठित तरीके से संचालित किया जा रहा था और इसमें कई लोगों की संलिप्तता हो सकती है। सभी आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।अधिकारियों ने आम जनता से अपील की है कि यदि कहीं भी अवैध शराब के परिवहन या बिक्री की जानकारी मिले तो तुरंत पुलिस को सूचित करें।पुलिस ने भरोसा दिलाया है कि जिले में अवैध शराब के पूरे नेटवर्क को खत्म करने के लिए लगातार कार्रवाई और निगरानी जारी रहेगी।

बड़े जुआरी गिरफ्तार, मर्सिडीज कार आईफ़ोन और 6 लाख नकदी जब्त

रायपुर। पुलिस द्वारा जुआरियों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही करते हुए थाना अभनपुर क्षेत्र अंतर्गत एक बड़ी रेड कार्यवाही की गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 06 अप्रैल 2026 को मुखबिर से सूचना मिली कि जिला रायपुर ग्रामीण एवं धमतरी की सीमा पर स्थित ग्राम टोकरो के पास खेतों के बीच कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा जुआ खेला जा रहा है। जनता से रिश्ता विगत कई दिनों रायपुर के आउटरों में स्थित फार्म हाउस में अवैध कारोबार संचालित होने की खबर प्रकाशित कर रहा है, जिसका असर देखने को मिला है, बड़े जुआरी पकड़े गए है और कई सफेदपोश जुआरी भाग खड़े हुए, लेकिन पुलिस ने अपने प्रेस विज्ञप्ति में फार्म हाउस का जिक्र नहीं किया है, सूत्रों के मुताबिक फार्म हाउस से नेता का संबंध होना बताया जा रहा है। जुए की इस फिल्ड से जुड़े 8 से 10 जुआरी जो बड़े घराने के और पहुंच वाले बताए जा रहे है। पुलिस ने बड़ी रकम लेकर उन सभी को भगाने में मदद की और छूटभैय्या नेताओं के चक्कर में पुलिस की रेड असफल साबित रही। सूचना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक के निर्देशन एवं डीएसपी नवा रायपुर के नेतृत्व में थाना अभनपुर पुलिस टीम द्वारा तत्काल मौके पर दबिश दी गई। पुलिस टीम को देखकर जुआ खेल रहे लोग भागने लगे, जिनमें से पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए 02 आरोपियों को दौड़ाकर पकड़ लिया, जबकि अन्य आरोपी अंधेरे एवं खेतों का फायदा उठाकर फरार हो गए।

रासायनिक खाद की कालाबाजारी करने वाले जेल जाएंगे

सरकार को है किसानों के हितों की चिंता:कृषिमंत्री रामविचार नेताम

- उर्वरक की नहीं होगी कमी, जैविक खेती के लिए किसानों को रहे हैं प्रोत्साहित
- अधिकारियों को नवाचार और फसल परिवर्तन पर जोर देने के निर्देश

रायपुर/ संवाददाता

छत्तीसगढ़ में रासायनिक उर्वरकों की कालाबाजारी करने वालों पर अब सख्त कार्रवाई तय है। कृषि मंत्री श्री रामविचार नेताम ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि खाद की जमाखोरी या अधिक मूल्य पर बिक्री करने वालों पर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं गड़बड़ी पाए जाने पर सीधे जेल भी भेजे जाएंगे। उन्होंने कहा कि पश्चिमी एशिया संकट के कारण रासायनिक उर्वरकों की कमी की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए सरकार पूरी तरह सजग है। खाद की कमी नहीं होगी। इसके साथ ही किसानों को जैविक खेती के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में आपूर्ति और बेहतर होगी, इसलिए किसानों को किसी भी प्रकार से घबराहट या पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। कृषि मंत्री श्री नेताम ने आज इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय परिसर स्थित समेति कक्ष में रायपुर और दुर्ग संभाग के अधिकारियों की आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान इस आशय के वक्तव्य दिए। मंत्री श्री नेताम ने बताया कि राज्य सरकार खरीफ 2026 की तैयारियों को लेकर पूरी तरह सक्रिय है और उर्वरक उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए लगातार निगरानी की जा रही है। जिलों के संबंधित विभागीय अमले को नियमित एवं आकस्मिक निरीक्षण के निर्देश दिए गए हैं, ताकि किसी भी स्तर पर अनियमितता सामने आते ही तत्काल कार्रवाई की जा सके। मंत्री श्री नेताम ने बैठक में आगामी 5 मई से 20 मई तक पूरे प्रदेश में विकसित भारत संकल्प अभियान की तैयारियों की भी समीक्षा की। उन्होंने कहा कि इस अभियान के तहत कृषि वैज्ञानिकों, विभागीय अधिकारियों और मैदानी अमले की टीम गांव-गांव जाकर किसानों, किसान समूहों और संगठनों से सीधे संवाद करेगी। इस दौरान किसानों को उन्नत कृषि तकनीकों, वैकल्पिक उर्वरकों और आधुनिक खेती के तरीकों की जानकारी दी जाएगी। अभियान के दौरान कृषि के साथ-साथ अन्य विभाग जैसे-मछली पालन, उद्यानिकी, पशुपालन, कृषि विज्ञान केन्द्र के विशेषज्ञ भाग लेंगे, जिसमें विभिन्न विभागीय योजनाओं का प्रचार-प्रसार तथा विभागीय प्रकरण तैयार करने हेतु निर्देशित किया। मंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि अभियान को प्राथमिकता और गंभीरता के साथ संचालित किया जाए, ताकि अधिक से अधिक किसानों तक योजनाओं का लाभ पहुंच सके। उन्होंने कहा कि यह अभियान केवल जागरूकता तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि मौके पर ही किसानों की समस्याओं का समाधान और योजनाओं से जोड़ने की प्रक्रिया भी सुनिश्चित की जाएगी। बैठक में यह भी स्पष्ट किया गया कि पिछले वर्ष डीएपी की आपूर्ति में आई बाधाओं को देखते हुए इस बार एनपीके, एसएसपी और अन्य वैकल्पिक उर्वरकों के उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। साथ ही जैविक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। सरकार का फोकस केवल उर्वरक उपलब्धता तक सीमित नहीं है, बल्कि खेती को अधिक टिकाऊ, लाभकारी और आधुनिक बनाने पर है। किसानों की आय बढ़ाने और लागत घटाने के उद्देश्य से दलहन, तिलहन और अन्य वैकल्पिक फसलों को बढ़ावा देने की रणनीति पर भी तेजी से काम किया जा रहा है। बैठक में फार्मर आई डी के तहत एग्रीस्टैक पोर्टल में पंजीयन हेतु शेष बचे हुए कृषकों का एक सप्ताह के भीतर पंजीयन करने हेतु निर्देश दिए गए ताकि कोई भी किसान पी.एम.किसान योजना से लाभान्वित होने से वंचित न रहे।

आरंग में 300 सीटर अत्याधुनिक ऑडिटोरियम निर्माण हेतु 8.66 करोड़ रूपए स्वीकृत मिली.....

- कैबिनेट मंत्री गुरु खुशवंत साहेब ने क्षेत्र को दी बड़ी सौगात
- विद्यार्थियों को नई दिशा देने के साथ-साथ उनकी प्रतिभा को निखारने का सशक्त माध्यम बनेगा

रायपुर/ संवाददाता

छत्तीसगढ़ शासन के उच्च शिक्षा विभाग द्वारा राज्य में शिक्षा अधोसंरचना को सुदृढ़ एवं आधुनिक बनाने की दिशा में लगातार ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। इसी क्रम में रायपुर जिले के आरंग स्थित शासकीय बद्रीप्रसाद लोधी महाविद्यालय परिसर में 300 सीटर अत्याधुनिक ऑडिटोरियम के निर्माण हेतु 866.28 लाख (आठ करोड़ छियासठ लाख अट्ठाईस हजार रुपये) की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। क्षेत्रीय विधायक एवं प्रदेश के मंत्री गुरु खुशवंत साहेब के नेतृत्व में यह स्वीकृति क्षेत्र में शिक्षा अधोसंरचना के सुदृढ़ीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इससे महाविद्यालय की आधारभूत संरचना को मजबूती मिलेगी और विद्यार्थियों को आधुनिक सुविधाएं प्राप्त होंगी। उक्त परियोजना वर्ष 2024-25 के बजट प्रावधानों के अंतर्गत स्वीकृत की गई है। इस संबंध में अपर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आदेश जारी किया गया है तथा वित्त विभाग की सहमति प्राप्त होने के पश्चात निर्माण कार्य शीघ्र प्रारंभ किया जाएगा। मंत्री श्री साहेब ने कहा कि प्रस्तावित ऑडिटोरियम आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित होगा, जिसमें सेमिनार, कार्यशाला, संगोष्ठी एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन के लिए आवश्यक सभी व्यवस्थाएं उपलब्ध रहेंगी। इससे विद्यार्थियों को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने के लिए बेहतर मंच मिलेगा और महाविद्यालय को नई पहचान प्राप्त होगी। उन्होंने आगे कहा कि आरंग विधानसभा क्षेत्र में शिक्षा के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। यह ऑडिटोरियम क्षेत्र के विद्यार्थियों को नई दिशा देने के साथ-साथ उनकी प्रतिभा को निखारने का सशक्त माध्यम बनेगा। मंत्री ने इस महत्वपूर्ण स्वीकृति के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री सहित उच्च शिक्षा विभाग के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य शासन के सहयोग से आरंग क्षेत्र में विकास कार्यों को निरंतर गति मिल रही है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि प्रदेश सरकार के मार्गदर्शन में शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में विकास की यह श्रृंखला आगे भी जारी रहेगी और क्षेत्रवासियों को इसका लाभ मिलेगा।

एक जिला एक उत्पाद योजना से बदली तस्वीर

- अदरक की खेती से दोगुना मुनाफा कमाया

रायपुर/ संवाददाता

सरकार की एक जिला एक उत्पाद योजना अब धरातल पर किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रही है। इसी क्रम में बालोद जिले के गुण्डरदेही विकासखंड अंतर्गत ग्राम बघमरा के युवा प्रगतिशील किसान श्री आकाश चंद्राकर ने अदरक की खेती के माध्यम से सफलता की एक नई मिसाल प्रस्तुत की है। पारंपरिक फसलों से आगे बढ़ते हुए आकाश चंद्राकर ने एक जिला एक उत्पाद योजना से प्रेरित होकर अपने लगभग ढाई एकड़ खेत में अदरक की खेती की शुरुआत की। वैज्ञानिक पद्धतियों और बेहतर प्रबंधन के साथ की गई इस खेती से उन्हें उत्कृष्ट उत्पादन प्राप्त हुआ। साथ ही बाजार में अदरक की अच्छी मांग के कारण उन्हें अपनी उपज का बेहतर मूल्य मिला, जिससे उनकी आय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। किसानों को प्रोत्साहित करने और खेती की लागत को कम करने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ शासन के उद्यानिकी विभाग द्वारा राज्य पोषित मसाला क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम के अंतर्गत आकाश चंद्राकर को लगभग 49 हजार रुपये का अनुदान प्रदान किया गया। इस वित्तीय सहयोग से उन्हें आधुनिक कृषि संसाधन जुटाने, गुणवत्तापूर्ण बीज एवं तकनीकों का उपयोग करने में सहायता मिली, जिसका सीधा लाभ उत्पादन और गुणवत्ता में दिखाई दिया।आकाश चंद्राकर बताते हैं कि अदरक की खेती उनके लिए समृद्धि का नया द्वार बनकर आई है। शासन से प्राप्त अनुदान ने उनका आत्मविश्वास बढ़ाया और उन्हें बेहतर उत्पादन हासिल करने के लिए प्रेरित किया। उनका मानना है कि सही मार्गदर्शन और योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन से खेती को लाभकारी बनाया जा सकता है। एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत अदरक को चयनित किए जाने के बाद जिले के अन्य किसान भी इस नगदी फसल की ओर आकर्षित हो रहे हैं। पारंपरिक फसलों की तुलना में अदरक से प्राप्त अधिक शुद्ध लाभ ने किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत किया है। जिला प्रशासन बालोद और उद्यानिकी विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जा रही तकनीकी सलाह एवं अनुदान से खेती अब घाटे का सौदा नहीं, बल्कि लाभ का माध्यम बनती जा रही है। श्री चंद्राकर ने केंद्र एवं राज्य सरकार की किसान हितैषी नीतियों को सराहना करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने विश्वास जताया कि शासन की इस पहल से बालोद जिला अदरक उत्पादन के क्षेत्र में एक नई पहचान स्थापित करेगा।

ऑस्ट्रेलियाई महावाणिज्यदूत संग सांसद बृजमोहन की अहम चर्चा

- सिरपुर से औद्योगिक विकास तक : भारत ऑस्ट्रेलिया सहयोग को नई दिशा देने की पहल

रायपुर। संवाददाता

छत्तीसगढ़ प्रवास पर राजधानी रायपुर पहुंचे ऑस्ट्रेलियाई महावाणिज्यदूत , श्री बर्नार्ड लिंच ने रायपुर सांसद एवं वरिष्ठ भाजपा नेता श्री बृजमोहन अग्रवाल से मुलाकात की। इस दौरान दोनों के बीच राज्य के समग्र विकास, निवेश संभावनाओं और सांस्कृतिक विरासत पर व्यापक एवं सार्थक चर्चा हुई।बैठक में छत्तीसगढ़ में औद्योगिक निवेश की संभावनाओं, प्राकृतिक संसाधनों के समुचित उपयोग तथा राज्य को एक उभरते औद्योगिक हब के रूप में विकसित करने के विषय पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया। सांसद श्री अग्रवाल ने सरकार द्वारा संचालित विकास और जनहित की योजनाओं की जानकारी दी। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ की समृद्ध हेरिटेज, कला, संस्कृति और पर्यटन की अपार संभावनाओं पर भी विस्तृत चर्चा हुई। श्री अग्रवाल ने विशेष रूप से विश्व धरोहर 'सिरपुर' का उल्लेख करते हुए बताया कि यह स्थल जैन धर्म की तपस्या, बौद्ध धर्म की शांति और सनातन संस्कृति के अटूट संगम का जीवंत प्रमाण है। यह ऐतिहासिक धरोहर न केवल भारत, बल्कि विश्व के पर्यटकों को आकर्षित करने की अपार क्षमता रखती है।श्री अग्रवाल ने छत्तीसगढ़ की अद्भुत प्राकृतिक संपदा का उल्लेख करते हुए कहा कि यह राज्य घने जंगलों, मनोरम पहाड़ियों, नदियों, शांत झीलों और जैव विविधता से परिपूर्ण प्राकृतिक सौंदर्य का अद्वितीय उदाहरण है। यहां का हर क्षेत्र प्रकृति की अनुपम छटा को समेटे हुए है, जो न केवल पर्यटकों को आकर्षित करता है।

शराब घोटाले में बड़ा खुलासा : 3 और वाहन जब्त, डिस्टलरी से अवैध सप्लाई का नेटवर्क बेनकाब

रायपुर। शराब घोटाले से जुड़ी जांच में लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। ताजा कार्रवाई में अवैध शराब परिवहन के मामले में 3 और वाहनों को जब्त किया गया है। यह कार्रवाई दुर्ग जिले के कुम्हारी स्थित डिस्टलरी से जुड़ी बताई जा रही है, जहां से अवैध तरीके से शराब की सप्लाई की जा रही थी।जांच एजेंसियों को मिले डिजिटल और भौतिक साक्ष्यों के आधार पर यह खुलासा हुआ है कि इन वाहनों के जरिए शासकीय शराब दुकानों तक अवैध शराब पहुंचाई जाती थी। इस पूरे नेटवर्क में परिवहन के लिए भरोसेमंद लोगों का इस्तेमाल किया जाता था, जिससे लंबे समय तक यह खेल बिना पकड़े चलता रहा।

आत्मनिर्भरता की मिसाल बनीं ग्रामीण महिलाएं

छत्तीसगढ़ में ग्रामीण महिलाएं गृह उद्योग और हस्तशिल्प से संवर रहा भविष्य

रायपुर/ संवाददाता

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (बिहान) के प्रभावी क्रियान्वयन से रायगढ़ जिले की ग्रामीण महिलाएं आज आत्मनिर्भरता की दिशा में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल कर रही हैं। यह योजना महिलाओं को न केवल आर्थिक रूप से सशक्त बना रही है, बल्कि उन्हें आत्मविश्वास, कौशल और सामाजिक पहचान भी प्रदान कर रही है। रायगढ़ जिले के ग्राम बड़ेभंडार की निवासी श्रीमती मथुरा कुर्रे इसकी उदाहरण हैं। उन्होंने बताया कि बिहान योजना से जुड़ने के पश्चात उन्हें रिवॉल्विंग फंड एवं कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड के तहत आर्थिक सहयोग प्राप्त हुआ। इस सहयोग से उन्होंने घर पर ही अचार, पापड़, बड़ी एवं मसाला निर्माण का कार्य प्रारंभ किया। आज वे अपने उत्पादों का बाजार में विक्रय कर नियमित आय अर्जित कर रही हैं, जिससे उनके परिवार की आर्थिक स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ है और वे आत्मनिर्भर बन सकी हैं। इसी क्रम में ग्राम रूमकेरा, तहसील घरघोड़ा की श्रीमती जमुना सिदार की कहानी भी प्रेरणादायक है। पूर्व में वे एक गृहिणी थीं, किन्तु बिहान योजना से जुड़ने के बाद उन्होंने बांस शिल्प का प्रशिक्षण प्राप्त किया। प्रशिक्षण उपरांत उन्होंने टोकरी, सूपा एवं अन्य हस्तशिल्प उत्पादों का निर्माण प्रारंभ किया। उन्हें विभिन्न मेलों, विशेषकर 'सरस मेला' में अपने उत्पादों के प्रदर्शन और विक्रय का अवसर प्राप्त हुआ, जिससे वे अच्छी आय अर्जित कर रही हैं। इससे उनके जीवन स्तर में सकारात्मक परिवर्तन आया है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन महिलाओं को केवल आर्थिक सहायता ही नहीं, बल्कि कौशल विकास, उद्यमिता और आत्मगौरव का अवसर भी प्रदान कर रहा है। जिले में अनेक महिलाएं इस योजना से जुड़कर स्वरोजगार के माध्यम से अपने जीवन को नई दिशा दे रही हैं। शासन के मंशानुरूप जिला प्रशासन रायगढ़ द्वारा महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण हेतु निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। विभिन्न योजनाओं से जोड़कर महिलाओं को स्वावलंबी बनाया जा रहा है, जिससे वे न केवल अपने परिवार की आय में वृद्धि कर रही हैं, बल्कि समाज में एक सशक्त भूमिका भी निभा रही हैं। बिहान योजना आज जिले में महिला सशक्तिकरण का सशक्त माध्यम बनी है, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करते हुए आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को साकार करने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है।

- सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर और निर्णयकारी भूमिका में स्थापित करने की दिशा में कार्य कर रही

भारत में महिला सशक्तिकरण का उद्देश्य महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से स्वतंत्र, शिक्षित और समान अधिकार संपन्न बनाना है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मुद्रा योजना और महिला आरक्षण जैसे प्रयासों से निर्णय लेने की प्रक्रिया में उनकी भागीदारी बढ़ी है। हालांकि, पितृसत्तात्मक सोच और सुरक्षा चुनौतियाँ अभी भी मौजूद हैं, लेकिन शिक्षा व कानूनी सुधारों से बदलाव आ रहा है। भारत में महिलाओं के सशक्तिकरण की सोच अब एक व्यापक और जीवन-चक्र आधारित दृष्टिकोण में विकसित हो चुकी है, जहाँ जन्म से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका और नेतृत्व तक महिलाओं की आवश्यकताओं को समग्र रूप से संबोधित किया जा रहा है। भारत सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाएँ अब केवल कल्याण तक सीमित नहीं रहीं, बल्कि वे महिलाओं को आत्मनिर्भर और निर्णयकारी भूमिका में स्थापित करने की दिशा में कार्य कर रही हैं। यह बदलाव वेलफेयर से एम्पावरमेंट और अब वूमेन-लेड डेवलपमेंट की ओर भारत की विकास यात्रा को दर्शाता है। स्वास्थ्य एवं पोषण के क्षेत्र में मिशन पोषण 2.0, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान जैसी पहलों ने महत्वपूर्ण सुधार सुनिश्चित किए हैं।

संपादकीय

सड़कें वही, लेकिन सफर हो रहा महंगा, यात्रियों की बढ़ी मुश्किलें

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा एकल और दोहरी यात्रा में पांच रुपए से लेकर पैंतीस रुपए तक की बढ़ोतरी पर सवाल उठना स्वाभाविक है।देशभर में महंगाई में बढ़ोतरी के बीच अब लोगों के लिए कहीं आना-जाना भी महंगा साबित होने लगा है। दरअसल, वैश्विक परिस्थितियों की वजह से पहले ही संकट का दायरा फैल रहा है और चीजों की कीमतों में इजाफा हो रहा है। इस बीच हरियाणा में राजमार्गों पर टोल दरों में बेतहाशा वृद्धि की घोषणा आम लोगों के सामने एक नई परेशानी पैदा करने वाली है। इसके अमल में आने के साथ ही निजी वाहनों से यात्रा करने वालों को अब अधिक टोल चुकाना होगा। यह हाल तब है, जबकि अधिकतर राजमार्गों पर बुनियादी सुविधाओं का घोर अभाव है, आए दिन लोगों को लंबे जाम का सामना करना पड़ता है।ऐसे में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा एकल और दोहरी यात्रा में पांच रुपए से लेकर पैंतीस रुपए तक की बढ़ोतरी पर सवाल उठना स्वाभाविक है। मसलन, गुरुग्राम में द्वारका एक्सप्रेस-वे पर बजघेड़ा टोल प्लाजा पर एकल यात्रा के लिए 225 रुपए देना यात्रियों के लिए भारी साबित हो सकता है। दूसरी ओर वाणिज्यिक वाहनों से वसूली का असर भी दिखेगा और आखिरकार आम आदमी पर ही इसकी मार पड़ेगी। सवाल है कि बुनियादी सुविधाओं में सुधार किए बिना टोल दरों में वृद्धि की क्या तुक है। नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत के साथ ही राजमार्गों पर यात्रा महंगी किए जाने से लोगों में निराशा बढ़ेगी।इस समय ज्यादातर राजमार्गों पर वाहनों का दबाव बढ़ रहा है। वहीं रास्ते में साफ-सुथरे जन-सुविधा परिसरों का अभाव खटकता है। रात में कई मार्गों पर अंधेरा होने से हादसे का अंदेशा बना रहता है। राजमार्ग प्राधिकरण के गश्ती दल तुरंत मौके पर नहीं पहुंचते। इससे लोग असहाय स्थिति में होते हैं। कई बार हादसे के बाद फिर हादसा होना यह बताता है कि प्राधिकरण को टोल की तो चिंता है, लेकिन यात्रियों की जान की नहीं। अक्सर देखा गया है कि टोल नाकों पर वाहनों की लंबी कतार लग जाती है।इससे न केवल समय की, बल्कि ईंधन की भी बर्बादी होती है। हालांकि हरियाणा में टोल पर अब केवल फास्टैग या आनलाइन भुगतान ही किया जा सकेगा। ऐसे में संभव है कि वाहनों की कतार कुछ कम हो। फिर भी राजमार्गों पर सुविधाएं बढ़ाए बिना टोल शुल्क बढ़ाना यात्रियों पर नाहक ही बोझ डालने जैसा है। शनिवार को नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के पहले चरण का उद्घाटन।इससे वाणिज्य और संपर्क को बढ़ावा मिलेगा। यह दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (आइजीआइ) पर भीड़भाड़ कम करेगा। नोएडा हवाई अड्डा भारत की सबसे बड़ी नई हवाई अड्डा परियोजनाओं में से एक है। हवाईअड्डे के पहले चरण को सार्वजनिक-निजी भागीदारी माडल के तहत 11,200 करोड़ की लागत से विकसित किया गया है। इस हवाईअड्डे की यात्री संभालने की क्षमता शुरुआत में प्रतिवर्ष 1.2 करोड़ यात्रियों की होगी। पूरी तरह विकसित होने पर इसे बढ़ाकर प्रतिवर्ष सात करोड़ यात्रियों तक बढ़ाया जा सकेगा। हवाई अड्डे की विशेषताओं में 3,900 मीटर लंबा रनवे शामिल है, जो चौड़े आकार के विमानों को संभालने में सक्षम है।

आधुनिकता के संक्रमणकालीन दौर में सबसे अधिक यदि कोई संस्था प्रश्नों के घेरे में है, तो वह विवाह और रिश्तों की पारंपरिक अवधारणा है। बदलती जीवनशैली, आर्थिक आत्मनिर्भरता, तकनीक, वैश्वीकरण और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बढ़ती चेतना ने रिश्तों की परिभाषा, अपेक्षाएँ और संरचना-सब कुछ बदल दिया है। यही कारण है कि आज रिश्तों से जुड़े प्रश्न केवल सामाजिक विमर्श का विषय नहीं रहे, बल्कि अदालतों तक पहुँच रहे हैं। हाल ही में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के दो फैसलों ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता और विवाह संस्था के बीच उत्पन्न हो रही नाजुक खाई को उजागर किया है।

विवाह संस्था और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बीच नई खाई

(ललित गर्ग)

पिछली पीढ़ियों में विवाह जीवन का अनिवार्य चरण माना जाता था। हमारे माता-पिता और दादा-दादी के लिए विवाह केवल दो व्यक्तियों का नहीं, बल्कि दो परिवारों का संबंध था और जीवन भर साथ निभाना ही उसका लक्ष्य था। लेकिन आधुनिक पीढ़ी रिश्तों को अलग दृष्टि से देख रही है।

आधुनिकता के संक्रमणकालीन दौर में सबसे अधिक यदि कोई संस्था प्रश्नों के घेरे में है, तो वह विवाह और रिश्तों की पारंपरिक अवधारणा है। बदलती जीवनशैली, आर्थिक आत्मनिर्भरता, तकनीक, वैश्वीकरण और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बढ़ती चेतना ने रिश्तों की परिभाषा, अपेक्षाएँ और संरचना-सब कुछ बदल दिया है। यही कारण है कि आज रिश्तों से जुड़े प्रश्न केवल सामाजिक विमर्श का विषय नहीं रहे, बल्कि अदालतों तक पहुँच रहे हैं। हाल ही में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के दो फैसलों ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता और विवाह संस्था के बीच उत्पन्न हो रही नाजुक खाई को उजागर किया है। एक निर्णय में न्यायालय ने कहा कि वयस्कों के बीच आपसी सहमति से बना लिव-इन रिलेशनशिप, भले ही एक साथी विवाहित हो, अपराध नहीं है; वहीं दूसरे मामले में न्यायालय ने ऐसे ही एक जोड़े को संरक्षण देने से इनकार कर दिया और कहा कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के नाम पर पति या पत्नी के कानूनी अधिकारों को कमजोर नहीं किया जा सकता। यह विरोधाभास वास्तव में न्यायिक असंगति से अधिक एक कानूनी रिक्तता और सामाजिक संक्रमण का संकेत है। वास्तव में एक हकीकत यह भी है कि भारतीय समाज में वैवाहिक अधिकारों और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बीच संतुलन बनाने वाले एक प्रभावी ढांचे की लंबे समय से आवश्यकता महसूस की जाती रही है। हमें मौजूदा परिदृश्य में यह बात स्वीकार करनी होगी कि यद्यपि विवाह संस्था संरक्षण की हकदार है, फिर भी पुरुष या स्त्री की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को अनिश्चित काल तक इसके अधीन बंधक बनाकर नहीं रखा जा सकता है।

निश्चित ही भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 प्रत्येक व्यक्ति को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है और इसी के दायरे में न्यायालयों ने समय-समय पर लिव-इन रिलेशनशिप को अपराध की श्रेणी से बाहर माना है। लेकिन दूसरी ओर, भारतीय कानून विवाह को एक कानूनी और सामाजिक संस्था के रूप में सर्वोच्च प्राथमिकता देता है, जिसमें अधिकार और दायित्व दोनों शामिल हैं। यही वह बिंदु है जहाँ व्यक्तिगत स्वतंत्रता और वैवाहिक अधिकारों के बीच टकराव उत्पन्न होता है। न्यायालय लिव-इन संबंधों को अपराध नहीं मानता, परंतु उनके सभी परिणामों को वैध मानने में संकोच करता है। यह स्थिति न केवल कानूनी भ्रम उत्पन्न करती है, बल्कि सामाजिक असुरक्षा भी पैदा करती है। वास्तव में समस्या न्यायिक निर्णयों की नहीं, बल्कि स्पष्ट विधायी ढाँचे की कमी की है। यदि व्यापक सामाजिक परिप्रेक्ष्य में देखें तो भारतीय समाज इस समय एक बड़े संक्रमणकाल से गुजर रहा है। एक ओर सदियों से स्थापित पारंपरिक जीवन मूल्य हैं, जिनमें विवाह केवल एक अनुबंध नहीं बल्कि एक संस्कार, सामाजिक स्वीकृति और पारिवारिक व्यवस्था का आधार है; दूसरी ओर आधुनिक जीवन की वास्तविकता है, जहाँ व्यक्ति की स्वतंत्रता, आत्म-विकास, करियर, आर्थिक स्वायत्तता और व्यक्तिगत संतुष्टि को भी समान महत्व दिया जा रहा है। विशेष रूप से महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता ने रिश्तों की

शक्ति-संतुलन व्यवस्था को बदल दिया है। अब रिश्ते केवल सामाजिक दबाव से नहीं, बल्कि आपसी समझ और संतुष्टि के आधार पर टिके रहते हैं। परिणामस्वरूप, रिश्तों की स्थायित्व की अवधारणा बदल रही है और प्रतिबद्धता अब आजीवन वचन से अधिक एक निरंतर पुनर्मूल्यांकन की प्रक्रिया बनती जा रही है।

पिछली पीढ़ियों में विवाह जीवन का अनिवार्य चरण माना जाता था। हमारे माता-पिता और दादा-दादी के लिए विवाह केवल दो व्यक्तियों का नहीं, बल्कि दो परिवारों का संबंध था और जीवन भर साथ निभाना ही उसका लक्ष्य था। लेकिन आधुनिक पीढ़ी रिश्तों को अलग दृष्टि से देख रही है। आज के युवा पहले शिक्षा, करियर और आर्थिक स्थिरता को प्राथमिकता देते हैं, उसके बाद रिश्तों के बारे में निर्णय लेते हैं। कुछ लोग विवाह से पहले साथ रहने का विकल्प चुनते हैं, कुछ रिश्तों को नाम देने से भी बचते हैं और कुछ लोग विवाह के बजाय साझेदारी को अधिक उपयुक्त मानते हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि आधुनिक पीढ़ी रिश्तों को महत्व नहीं देती, बल्कि इसका अर्थ यह है कि वे रिश्तों में स्वतंत्रता, सम्मान, संवाद और समानता को अधिक महत्व देते हैं। रिश्तों में सबसे बड़ा परिवर्तन लिंग भूमिकाओं के बदलाव से भी आया है। पहले पुरुष कमाने वाला और महिला घर संभालने वाली मानी जाती थी, लेकिन आज दोनों काम करते हैं, दोनों निर्णय लेते हैं और दोनों भावनात्मक सहयोग चाहते हैं। आधुनिक रिश्तों में समानता, खुलकर संवाद और साझा जिम्मेदारियों पर जोर है। हालांकि पुरुष और महिलाओं की अपेक्षाएँ पूरी तरह समान नहीं होतीं- अक्सर महिलाएँ भावनात्मक सहयोग और संवाद को अधिक महत्व देती हैं, जबकि पुरुष स्वतंत्रता और बौद्धिक जुड़ाव को महत्वपूर्ण मानते हैं लेकिन इन अंतरों को समझकर ही मजबूत रिश्ते बनाए जा सकते हैं।

आज आत्म-प्रेम और आत्म-देखभाल को स्वार्थ नहीं, बल्कि स्वस्थ जीवन का आधार माना जाने लगा है। तकनीक और सोशल मीडिया ने भी रिश्तों की प्रकृति को गहराई से प्रभावित किया है। सोशल मीडिया ने लोगों को जोड़ने का काम किया है, लेकिन इसके साथ तुलना की संस्कृति भी बढ़ी है। अब लोग अपने रिश्तों की तुलना दूसरों की ऑनलाइन तस्वीरों और पोस्ट से करने लगे हैं, जिससे असंतोष और अवास्तविक अपेक्षाएँ बढ़ती हैं। कई बार डिजिटल दुनिया में मिलने वाला ध्यान वास्तविक रिश्तों की आत्मीयता को कम कर देता है। ऑनलाइन फ्लर्टिंग, डिजिटल बेवफाई और लगातार उपलब्ध रहने की अपेक्षा जैसी नई समस्याएँ भी सामने आई हैं। इसलिए आज डिजिटल सीमाएँ भी उतनी ही आवश्यक हो गई हैं जितनी व्यक्तिगत सीमाएँ।

ऑनलाइन डेटिंग ने रिश्तों की दुनिया को पूरी तरह बदल दिया है। जीवनसाथी ढूँढना पहले परिवार, समाज या परिचितों के माध्यम से होता था, लेकिन अब मोबाइल एप और वेबसाइटों के माध्यम से लोग साथी ढूँढते हैं। इससे विकल्प बढ़े हैं, लेकिन साथ ही रिश्तों की स्थिरता कम हुई है। 'स्वाइप संस्कृति' ने रिश्तों को कई बार उपभोक्ता वस्तु की तरह बना दिया है, जहाँ विकल्प हमेशा खुले रहते हैं और प्रतिबद्धता कठिन हो जाती है। इसके बावजूद, यह भी सत्य है कि कई सफल विवाह और रिश्ते भी ऑनलाइन माध्यम से ही बने हैं। इसलिए समस्या तकनीक में नहीं, बल्कि उसके उपयोग की मानसिकता में है। आज की तेज़ रफ्तार दुनिया में रिश्तों को समय देना भी एक बड़ी चुनौती बन गया है। करियर, प्रतिस्पर्धा, आर्थिक दबाव, सोशल मीडिया और व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएँ- इन सबके बीच रिश्ते अक्सर प्राथमिकता सूची में नीचे चले जाते हैं। लेकिन यह भी एक सत्य है कि अंततः मनुष्य को भावनात्मक सहारा, अपनापन और संबंधों की ही आवश्यकता होती है। इसलिए आधुनिक जीवन में रिश्तों को बनाए रखने के लिए संवाद, समय, सम्मान और समझ पहले से कहीं अधिक आवश्यक हो गए हैं।

विभिन्न पीढ़ियों के बीच रिश्तों को लेकर दृष्टिकोण में भी बड़ा अंतर दिखाई देता है। पुरानी पीढ़ी स्थायित्व और त्याग को महत्व देती है, जबकि नई पीढ़ी संतुष्टि और स्वतंत्रता को। पुरानी पीढ़ी रिश्ते बचाने के लिए समझौता करती थी, नई पीढ़ी रिश्ते में सम्मान और खुशी नहीं मिलने पर उसे छोड़ने का साहस रखती है। दोनों दृष्टिकोणों में अपनी-अपनी सच्चाई है। इसलिए आवश्यकता पीढ़ियों के संघर्ष की नहीं, बल्कि संवाद और समझ की है। वास्तव में विवाह बनाम स्वतंत्रता का प्रश्न किसी एक पक्ष की जीत या हार का प्रश्न नहीं है। यह समाज के विकास और परिवर्तन का स्वाभाविक चरण है। विवाह संस्था समाज के लिए आवश्यक है, क्योंकि वह स्थिरता, परिवार और सामाजिक व्यवस्था का आधार है। लेकिन व्यक्तिगत स्वतंत्रता भी उतनी ही आवश्यक है, क्योंकि बिना स्वतंत्रता के कोई भी रिश्ता केवल बंधन बन जाता है। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि कानून, समाज और परिवार-तीनों मिलकर ऐसा संतुलन बनाएं, जिसमें विवाह संस्था भी सुरक्षित रहे और व्यक्ति की स्वतंत्रता भी सुरक्षित रहे। निश्चिततौर पर यह स्वीकार करना होगा कि जब रिश्ते टूट जाते हैं, तो व्यक्तियों को गरिमा के साथ आगे बढ़ने की अनुमति देना समाज के लिए खतरा नहीं है, बल्कि यह सामाजिक व्यवस्था का एक आवश्यक अनुकूलन है। दुनिया तेजी से बदल रही है।

अगर ईरान युद्ध 40 दिन खिंचा तो खाने-पीने की चीजों का हो सकता है संकट, एफएओ ने दी चेतावनी

(दिल प्रकाश)

ईरान युद्ध को एक महीने से अधिक समय हो चुका है और इसके फिलहाल खत्म होने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। इससे दुनिया भर में खाने-पीने की चीजों की कीमत में मार्च में काफी तेजी आई और यह पिछले साल सितंबर के बाद सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई। इसकी वजह यह है कि हाल में तेल और गैस की कीमत में काफी तेजी आई है। यूनाइटेड नेशंस की संस्था फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गनाइजेशन (एफएओ) का कहना है कि अगर ईरान युद्ध जारी रहा तो खाने-पीने की चीजों की कीमत में आगे और इजाफा हो सकता है।

रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक एफएओ के चीफ इकनॉमिस्ट मक्सिमो तोरेरो ने कहा कि ईरान युद्ध शुरू होने के बाद खाने-पीने की चीजों की कीमत में मामूली तेजी आई है। कच्चे तेल की कीमत में तेजी इसकी वजह है। लेकिन दुनिया में अनाज की पर्याप्त सप्लाई के कारण कीमतों में ज्यादा उछाल नहीं आई है। अगर लड़ाई 40 दिन से ज्यादा खिंचती है और कच्चे माल की कीमत हाई बनी रहती है तो किसान बुवाई का रकबा कम कर सकते हैं और ऐसी फसलों का रुख कर सकते हैं जिनमें कम फर्टिलाइजर का यूज होता है।

उत्पादन पर असर: तोरेरो ने कहा कि अगर किसान ऐसा करते हैं तो इससे भविष्य में उत्पादन पर असर पड़ेगा और आने वाले दिनों में फूड सप्लाई और कमोडिटी की कीमतों पर असर हो सकता है। एफएओ का फूड प्राइस इंडेक्स फरवरी के मुकाबले मार्च में 2.4 फीसदी बढ़ गया। यह पिछले साल के मुकाबले 1 फीसदी ऊपर है।

हालांकि यह मार्च 2022 के पीक के मुकाबले करीब 20 फीसदी नीचे है। यूक्रेन युद्ध की शुरुआत में यह इस स्तर पर पहुंचा था।

अनाज की कीमत बताने वाला इंडेक्स फरवरी की तुलना में मार्च में 1.5 फीसदी चढ़ गया। इसकी वजह यह है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गेहूं की कीमत में 4.3 फीसदी तेजी आई है। अमेरिका में फसल खराब होने की आशंका और फर्टिलाइजर संकट के कारण ऑस्ट्रेलिया में कम बुवाई के कारण ऐसा हुआ है। मक्के की कीमत में मामूली तेजी आई है जबकि कमजोर मांग के कारण चावल की कीमत 3 फीसदी गिरी है।

वेजिटेबल ऑयल की कीमत: वेजिटेबल ऑयल की कीमत 5.1 फीसदी बढ़ी है। लगातार तीसरे महीने इसमें तेजी आई है। पाम ऑयल 2022 के मध्य के बाद उच्चतम स्तर पर पहुंच चुका है। शुगर की कीमत में मार्च में 7.2 फीसदी तेजी आई जो पिछले साल अक्तूबर के बाद सबसे ज्यादा है। माना जा रहा है कि कच्चे तेल की कीमत बढ़ने से ब्राजील ज्यादा एथेनॉल बना सकता है। ब्राजील दुनिया में चीनी का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। मार्च में मीट की कीमत में 1 फीसदी तेजी आई। यूरोप में सुअर की मीट और ब्राजील में पशुओं की मीट की कीमत बढ़ी है जबकि पॉल्ट्री की कीमत में गिरावट आई है। एक अलग रिपोर्ट में एफएओ ने 2025 के लिए दुनिया में अनाज उत्पादन का अनुमान बढ़ाकर रेकॉर्ड 3.036 अरब टन कर दिया। यह पिछले साल के मुकाबले 5.8 फीसदी अधिक है।

(यह लेखक के अपने विचार है)

आखिर पश्चिम बंगाल में 'चुनावी जंगलराज' के लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई क्यों नहीं?

पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया के दौरान 7 न्यायिक अधिकारियों, जिनमें 3 महिलाएं भी शामिल थीं, के साथ हुई दुर्व्यवहार की घटना वहां के कानून-व्यवस्था और चुनावी प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाती है। चूंकि राज्य में चुनावी प्रक्रिया चल रही है और राज्य प्रशासन चुनाव आयोग के अधीन है, इसलिए मौजूदा स्थिति के लिए ममता सरकार को दोषी ठहराना न्यायोचित नहीं है। दरअसल, मालदा के कयाचक क्षेत्र में वोटर लिस्ट से नाम हटाए जाने के विरोध में सैकड़ों लोगों ने 1 अप्रैल 2026 को दोपहर 3:30 बजे से 9 घंटे से अधिक समय तक अधिकारियों को घेर लिया। प्रदर्शनकारियों ने बीडीओ कार्यालय में अधिकारियों को बंधक बनाया, जहां उन्हें भोजन-पानी के बिना रखा गया।

(कमलेश पांडे)

वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने मालदा घटना पर पश्चिम बंगाल सरकार को कड़ी फटकार लगाई, और इसे न्यायिक अधिकारियों को डराने-धमकाने की सुनियोजित साजिश और अदालत के अधिकार को खुली चुनौती बताया। कोर्ट ने राज्य प्रशासन की निष्क्रियता पर सख्ती दिखाते हुए इसे कानून-व्यवस्था की पूर्ण विफलता करार दिया।

पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया के दौरान 7 न्यायिक अधिकारियों, जिनमें 3 महिलाएं भी शामिल थीं, के साथ हुई दुर्व्यवहार की घटना वहां के कानून-व्यवस्था और चुनावी प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाती है। चूंकि राज्य में चुनावी प्रक्रिया चल रही है और राज्य प्रशासन चुनाव आयोग के अधीन है, इसलिए मौजूदा स्थिति के लिए ममता सरकार को दोषी ठहराना न्यायोचित नहीं है।

दरअसल, मालदा के कयाचक क्षेत्र में वोटर लिस्ट से नाम हटाए जाने के विरोध में सैकड़ों लोगों ने 1 अप्रैल 2026 को दोपहर 3:30 बजे से 9 घंटे से अधिक समय तक अधिकारियों को घेर लिया। प्रदर्शनकारियों ने बीडीओ कार्यालय में अधिकारियों को बंधक बनाया, जहां उन्हें भोजन-पानी के बिना रखा गया। सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पत्र पर स्वतः संज्ञान लिया। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य के मुख्य सचिव, गृह सचिव, डीजीपी, मालदा डीएम व एसपी को कारण बताओ (शो-कॉज) नोटिस जारी किया और 6 अप्रैल को ऑनलाइन सुनवाई बुलाई।

सुप्रीम कोर्ट ने इसे नागरिक व पुलिस प्रशासन की पूर्ण विफलता बताया तथा सीबीआई या एनआईए से जांच के निर्देश दिए, जिसे चुनाव आयोग ने सीबीआई को सौंप दिया। यह घटना न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर हमले के रूप में देखी जा रही है, जिसके राजनीतिक मायने खतरनाक हैं, क्योंकि

बीजेपी ने टीएमसी पर भीड़ भड़काने का आरोप लगाया, साथ ही इसे लॉ एंड ऑर्डर की विफलता और नकली वोटरों के नाम डिलीट होने का डर बताया। वहीं, टीएमसी ने बीजेपी व चुनाव आयोग को जिम्मेदार ठहराया, और एसआईआर को गंदी साजिश कहा। उल्लेखनीय है कि आगामी विधानसभा चुनावों (23-29 अप्रैल) से ठीक पहले इस विवाद के उभरने से राजनीतिक ध्रुवीकरण तेज हुए हैं।

वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने मालदा घटना पर पश्चिम बंगाल सरकार को कड़ी फटकार लगाई, और इसे न्यायिक अधिकारियों को डराने-धमकाने की सुनियोजित साजिश और अदालत के अधिकार को खुली चुनौती बताया। कोर्ट ने राज्य प्रशासन की निष्क्रियता पर सख्ती दिखाते हुए इसे कानून-व्यवस्था की पूर्ण विफलता करार दिया। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा, यह कोई सामान्य विरोध नहीं, बल्कि एसआईआर की प्रक्रिया को बाधित करने का पूर्वनियोजित प्रयास था। इससे प्रशासन की भूमिका पर सवाल उठते हैं। आखिर रात 11 बजे तक डीएम-एसपी क्यों नहीं पहुंचे? जब राजनीतिक नेता मौके पर थे तो प्रशासन क्यों सो रहा था? इसे न्यायपालिका पर हमला बताते हुए घिनौना प्रयास कहा, जो चुनावी प्रक्रिया को पटरी से उतारने का मकसद रखता था।

ततपश्चात कोर्ट ने मुख्य सचिव, डीजीपी, मालदा डीएम-एसपी को कारण बताओ (शो-कॉज) नोटिस जारी किया और 6 अप्रैल को सुनवाई बुलाई। वहीं, चुनाव आयोग को एसआईआर से जुड़े अधिकारियों की सुरक्षा के लिए केंद्रीय बल तैनात करने तथा भीड़ नियंत्रण (5 से अधिक लोगों पर रोक) के निर्देश दिए। साथ ही सीबीआई/एनआईए जांच का सुझाव भी दिया।

पश्चिम बंगालकी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मालदा घटना पर चुनाव आयोग को दोषी ठहराते हुए कहा कि राज्य प्रशासन उनके नियंत्रण में नहीं रहा। उन्होंने दावा किया कि उन्हें घटना की जानकारी आधी रात को एक पत्रकार से मिली और एसआईआर प्रक्रिया से लोगों का गुस्सा जायज है। ममता ने कहा, मुझे नहीं पता वे कौन थे जिन्होंने अधिकारियों का घेराव किया, लेकिन एसआईआर से लोग नाराज हैं। उन्होंने चुनाव आयोग पर आरोप लगाया कि चुनाव से पहले शीर्ष अधिकारियों के तबादले से सुपर राष्ट्रपति शासन चल रहा है। बीजेपी को जिम्मेदार बताते हुए जांच की मांग की और कहा, मेरी सारी शक्तियां छीन ली गई। ममता का यह बयान सागरदिघी या धूमुरपहाड़ी रैली में आया, जहां उन्होंने टीएमसी को निर्दोष बताया। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद यह चुनाव आयोग व बीजेपी पर हमला है, जो आगामी चुनावों में ध्रुवीकरण बढ़ा रहा है।

बेहतर होगा कि इस मामले में केंद्रीय मुख्य चुनाव आयुक्त, राज्य के पुलिस महानिदेशक और मुख्य सचिव के अलावा मालदा डीएम, एसपी को अविलंब नौकरी से बर्खास्त किया जाना चाहिए, क्योंकि चुनावी दिनों में इन सबकी अविवेकी हरकतों से एक निर्वाचित सरकार की बदनामी बढ़ी है, और इसके चुनावी दुष्प्रभाव से इनकार नहीं किया जा सकता है। वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे प्रशासनिक विफलता और आपराधिक अवमानना करार देते हुए कड़ी फटकार लगाई है। यह कितनी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर राज्य में सक्रिय न्यायिक अधिकारियों को सुरक्षा प्रदान करने में राज्य प्रशासन ने घोर कोताही बरती। यह महाजंगल राज नहीं तो क्या है? आखिर ऐसी नौबत क्यों आई, शोध का विषय है। उचित तो यह होगा कि इस उपद्रव में शामिल लोगों के व्यवहार को अराजक घोषित करते हुए इनके मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशनकार्ड आदि जब्त किया जाए और तमाम सरकारी सुविधाओं से ऐसे उग्र लोगों को वंचित किया जाए। साथ ही इन्हें उकसाने वाले राजनीतिक दलों की मान्यता रद्द की जाए और इसके प्रदेश अध्यक्ष को अविलंब गिरफ्तार किया जाए। यदि ऐसी सख्त कार्रवाई होगी, तभी भारत में स्वस्थ लोकतंत्र बहाल किया जा सकता है, अन्यथा नहीं! देखा जाए तो पहले दिल्ली में आप पार्टी की केजरीवाल सरकार और अब पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की ममता सरकार के खिलाफ केंद्रीय प्रशासनिक अधिकारियों का जिस तरह से दुरुपयोग किया जा रहा है और राज्य प्रशासन के अधिकारियों के साथ उनके नीतिगत काउंटर हो रहे हैं, उसे कतई निष्पक्ष करार नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि चुनी हुई सरकारों को %बर्बरतापूर्ण% तरीके से हटाने की सियासी परिस्थिति पैदा करने में इनकी अहम भूमिका है। केंद्र और राज्य प्रशासन में सक्रिय पक्षपाती तत्वों की शिनाख्त होनी चाहिए, क्योंकि जो हो रहा है, वह अस्वीकार्य है। यह संवैधानिक और न्यायिक विफलता है और इसके पीछे सम्बन्धित अधिकारियों की सियासी मिलीभगत की जांच होनी चाहिए। ताकि कानून का शासन बहाल हो और राजनीतिक नंगानाच पर लगाम लगे। यक्ष प्रश्न है कि आखिर पश्चिम बंगाल में चुनावी जंगलराज के लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई क्यों नहीं?(लेखक वरिष्ठ पत्रकार व राजनीतिक विश्लेषक (इस लेख में लेखक के अपने विचार हैं।)

नियमों का पालन करने वालों को पुष्पगुच्छ देकर किया गया सम्मान

सड़क दुर्घटनाओं पर पूर्ण नियंत्रण के ध्येय से नारायणपुर पुलिस ने चलाया यातायात अभियान

नारायणपुर। पुलिस द्वारा सड़क दुर्घटनाओं पर पूर्ण नियंत्रण के ध्येय से व्यापक यातायात अभियान एवं सघन चेकिंग अभियान संचालित किया गया। यह अभियान पुलिस अधीक्षक रोबिनसन गुड़िया के निर्देशन में जिला मुख्यालय सहित समस्त थाना क्षेत्रों में प्रभावी रूप से चलाया गया। अभियान के दौरान यातायात नियमों का पालन करने वाले वाहन चालकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से हेलमेट पहनकर दोपहिया वाहन चलाने वाले एवं सीट बेल्ट लगाकर चारपहिया वाहन चलाने वाले चालकों को पुष्पगुच्छ भेंट कर सम्मानित किया गया, वहीं अन्य वाहन चालकों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करते हुए हेलमेट एवं सीट बेल्ट के अनिवार्य उपयोग के संबंध में समझाइश दी गई। जिला पुलिस द्वारा आम नागरिकों से अपील की गई है कि वे स्वयं की सुरक्षा एवं दूसरों के जीवन की रक्षा हेतु यातायात नियमों का कड़ाई से पालन करें तथा इस अभियान में सक्रिय सहयोग प्रदान करें। पुलिस अधीक्षक गुड़िया ने बताया कि जनजागरूकता अभियान के पश्चात शीघ्र ही यातायात नियमों के उल्लंघन पर सख्ती से चालानी कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चलाने, बिना सीट बेल्ट चारपहिया वाहन चलाने, बाइक में तीन सवारी बैठाने तथा नशे की हालत में वाहन चलाने वालों के विरुद्ध किसी भी स्थिति में नरमी नहीं बरती जाएगी। इसी क्रम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार नायक के मार्गदर्शन एवं यातायात प्रभारी (रक्षित निरीक्षक) मोहसिन खान के नेतृत्व में 05 अप्रैल को राष्ट्रीय राजमार्ग 130डी गढ़बेगांल तिराहा में सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान विशेष रूप से मालवाहक वाहनों में सवारी बैठाने, बिना हेलमेट, बिना सीट बेल्ट वाहन चलाने तथा भारी वाहनों के दस्तावेजों की गहन जांच की गई। अभियान के अंतर्गत मालवाहक वाहनों में सवारी बैठाने वाले कुल 15 वाहन चालकों पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्यवाही किया गया, वहीं सघन वाहन चेकिंग के दौरान कुल 40 वाहन चालकों के खिलाफ कार्यवाही किया गया। चेकिंग के दौरान कई वाहनों के दस्तावेज सही पाए गए, जबकि कुछ में मामूली त्रुटि पाए जाने पर संबंधित चालकों को चेतावनी देकर छोड़ा गया।

पुलिस अधीक्षक गुड़िया ने वाहन चालकों से अपील की है कि वे मालवाहक वाहनों में सवारी न बैठाएं तथा सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम एवं यातायात व्यवस्था के सुचारू संचालन में सहयोग करें। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुशील नायक ने भी वाहन चालकों से आग्रह किया कि वे सदैव हेलमेट एवं सीट बेल्ट का उपयोग करें, नशे की हालत में वाहन न चलाएं, नाबालिगों को वाहन न चलाने दें, वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग न करें तथा यातायात संकेतों का पालन करें। आपकी सुरक्षा, हमारी जिम्मेदारी; यातायात नियमों का पालन है बड़ी समझदारी।

समय-सीमा बैठक में कलेक्टर के निर्देश, 14 अप्रैल से 'स्वस्थ बस्तर अभियान' होगा प्रारंभ

जगदलपुर। कलेक्टर आकाश छिकारा ने समय-सीमा की बैठक में राज्य शासन से प्राप्त निर्देशों के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर देते हुए कहा कि 14 अप्रैल से जिले में स्वस्थ बस्तर अभियान चलाया जाएगा, जिसके अंतर्गत घर-घर स्वास्थ्य जांच की जाएगी तथा इसका व्यापक प्रचार-प्रसार विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में सुनिश्चित किया जाए। कलेक्टर छिकारा ने जिला कार्यालय के प्रेरणा सभाकक्ष में आयोजित साप्ताहिक समय सीमा की बैठक ली। बैठक में स्वास्थ्य विभाग से एम्बुलेंस व्यवस्था, सौ दिन टीबी टेस्टिंग की निक्षय पोर्टल पर प्रगति तथा अस्पतालों में आयुष्मान कार्ड ब्लॉकिंग की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने ऑनलाइन पोस्टमार्टम रिपोर्ट व्यवस्था लागू करने पर चर्चा की ताकि आरबीसी 6-4 के प्रकरणों में आवश्यक सहायता सुनिश्चित की जा सके। उन्होंने उचित मूल्य की दुकानों में खाद्यान्न भंडारण की स्थिति पर संज्ञान लेते हुए सभी एसडीएम को प्रमुख एफसीआई गोदामों का निरीक्षण करने और पीडीएस संचालकों की तहसीलवार मासिक समीक्षा बैठक आयोजित करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने अक्रियाशील खातों से राशि जमा करवाने हेतु संबंधित अधिकारियों को प्राथमिकता के साथ कार्यवाही करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने समय-सीमा की बैठक में अनुपस्थित रहने वाले अधिकारियों पर नाराजगी जताते हुए स्पष्टीकरण जारी करने के निर्देश दिए। कृषि विभाग को शासन के निर्देशानुसार खाद्य विक्रेताओं की दुकानों में मानकों के अनुरूप विक्रय करने की जांच करने तथा एसडीएम को भी दुकानों का निरीक्षण सुनिश्चित करने को कहा। बैठक मे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत आधार सीडिंग एवं ई-केवाईसी, एग्रीस्टैक वेरिफिकेशन की भी समीक्षा की गई। कलेक्टर ने एनसीईएआर सर्वे, जनगणना की प्रारंभिक तैयारियों एवं मुख्य सचिव की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के निर्देशों के पालन की समीक्षा भी बैठक में की। आकांक्षी ब्लॉकों में सम्पूर्णता अभियान 2.0 के चार प्रमुख पैरामीटरों पर चर्चा करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

वन मंत्री केदार कश्यप ने किया कन्या छात्रावास भवन का उद्घाटन

नारायणपुर। प्रदेश के वन एवं जलवायु परिवर्तन, परिवहन, सहकारिता एवं संसदीय कार्य मंत्री केदार कश्यप ने अपने एक दिवसीय नारायणपुर प्रवास के दौरान आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग अंतर्गत एजुकेशन हब गरांजी में नव निर्मित पोस्ट मैट्रिक अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या छात्रावास भवन का उद्घाटन किया। कलेक्टर नम्रता जैन ने जानकारी दी कि छात्रावास भवन का निर्माण लगभग 1 करोड़ 91 लाख 51 हजार रुपये की लागत से हुआ है। छात्रावास के प्रारंभ होने से क्षेत्र की छात्राओं को सुरक्षित, सुविधायुक्त एवं गुणवत्तापूर्ण आवासीय व्यवस्था उपलब्ध होगी, जिससे उनकी शिक्षा में निरंतरता और गुणवत्ता दोनों में सुधार आएगा। यह सुविधा विशेष रूप से दूरस्थ एवं आदिवासी क्षेत्रों की छात्राओं के लिए उच्च शिक्षा को सुगम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इस दौरान वन मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा के क्षेत्र में विशेष रूप से बालिकाओं के सशक्तिकरण को प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने कहा कि दूरस्थ अंचलों में रहने वाली छात्राओं को आवासीय सुविधाओं के अभाव में उच्च शिक्षा प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, ऐसे में इस प्रकार के छात्रावास न केवल शिक्षा को सुलभ बनाएंगे, बल्कि उन्हें सुरक्षित और अनुकूल वातावरण भी प्रदान करेंगे। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इस पहल से छात्राओं की शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा और समाज में जागरूकता तथा सशक्तिकरण की दिशा में सकारात्मक परिवर्तन आएगा। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ के अध्यक्ष रूपसाय सलाम, जिला पंचायत अध्यक्ष नारायण मरकाम, नगर पालिका अध्यक्ष इंद्रप्रसाद बघेल, उपाध्यक्ष जयप्रकाश शर्मा, पार्षदगण, जनप्रतिनिधिगण और मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत आकांक्षा शिक्षा खलखो, अपर कलेक्टर बीरेंद्र बहादुर पंचभाई, एसडीएम अभयजीत मण्डावी, सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग डॉ. राजेंद्र सिंह, जिला शिक्षा अधिकारी अशोक कुमार पटेल सहित अन्य अधिकारी, कर्मचारी और छात्राएँ मौजूद रहे।

नक्सल प्रभाव खत्म, बंदूक की जगह अब खेती और खुशहाली

लाल आतंक के साये से निकलकर विकास की नई इबारत लिख रहा मिनपा

कोंटा। कभी नक्सलवाद का गढ़ और संघर्षों के लिए पहचाना जाने वाला मिनपा गांव शांति और सुशासन की नई मिसाल पेश कर रहा है। मार्च 2020 की वह हृदयविदारक घटना, जिसमें 17 सुरक्षाकर्मियों ने अपनी शहादत दी थी, उस काले अध्याय को पीछे छोड़ते हुए मिनपा अब विकास की मुख्यधारा से जुड़कर 'आत्मनिर्भरता' की ओर कदम बढ़ा चुका है।

स्वास्थ्य क्रांति-अब गांव में ही मिलता है उपचार – अतीत में ग्रामीणों को छोटी-छोटी बीमारियों के इलाज के लिए चिंतागुफा या दोरनापाल जैसे दूर-दराज के इलाकों पर निर्भर रहना पड़ता था। लेकिन आज गांव में ही उप स्वास्थ्य केंद्र स्थापित हो चुका है, जहाँ ग्रामीणों को निःशुल्क दवाएं और त्वरित उपचार मिल रहा है। स्वास्थ्य केंद्र में बाइक एंबुलेंस की सुविधा दी जा रही है जो दूरस्थ पहुँच विहीन गांवों से मरीजों को स्वास्थ्य केंद्र लाने का कार्य करती है।

डिजिटल सेवा: गांव में खुला आधार केंद्र – प्रशासन की सक्रियता से अब ग्रामीणों को शासकीय दस्तावेजों के लिए शहर की दौड़ नहीं लगानी पड़ती। गांव में ही आधार कार्ड अपडेट, जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र, राशन कार्ड और वोटर आईडी जैसी ऑनलाइन सुविधाएं सुलभ करा दी गई हैं।

शिक्षा और पोषण का उजियारा – मिनपा में अब स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र पूरी जीवंतता के साथ संचालित हैं। बच्चों के हाथों में अब किताब और कलम है, जो एक सुरक्षित और शिक्षित भविष्य की नींव रख रहे हैं।

सुदृढ़ राशन व्यवस्था और बिजली की पहुंच- गांव में निर्मित नए पीडीएस भवन से हर माह नियमित राशन वितरण सुनिश्चित हो रहा है। वहीं, बिजली के खंभों ने गांव के अंधेरे को दूर कर दिया है। घर-घर बिजली पहुंचाने का कार्य अब अंतिम चरण में है, जिससे गांव की रातें भी अब रोशन हैं।

कलेक्टर अमित कुमार ने बताया कि मिनपा गांव में विकास की यह नई बयार ग्रामीणों के जिला प्रशासन के प्रति बढ़ते विश्वास का परिणाम है। हमारा मुख्य उद्देश्य नक्सलवाद के खात्मे के साथ दूरस्थ क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं को सुदृढ़ करना है। आज मिनपा में स्कूल, बिजली, राशन और स्वास्थ्य सुविधाओं का सुलभ होना इस बात का प्रमाण है कि विकास अब अंतिम व्यक्ति तक पहुँच रहा है। हम मिनपा की तरह जिले के हर अंदरूनी गांव को मुख्यधारा से जोड़ने और वहां के युवाओं को बेहतर भविष्य देने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

मिनपा निवासी माड़वी सुक्का पिता भीमा को शासन द्वारा 2 हेक्टेयर रकबे का वनाधिकार पत्र प्रदान किया गया है, जिससे उन्हें अपने कब्जे की वन भूमि पर मालिकाना हक मिला। वनाधिकार पट्टे की भूमि पर माड़वी सुक्का ने धान की खेती कर आय बढ़ाई और छत्तीसगढ़ शासन की समर्थन मूल्य धान खरीदी योजना के तहत धान बेचकर प्राप्त राशि से ट्रैक्टर की किश्त चुकाई। साथ ही उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत पक्का मकान निर्माण की स्वीकृति मिली है और उनका आवास निर्माण कार्य प्रगति पर है। इसके अतिरिक्त उनके आधार कार्ड, राशन कार्ड, जॉब कार्ड, आयुष्मान कार्ड और पैन कार्ड भी बन चुके हैं, जिससे उन्हें विभिन्न शासकीय योजनाओं का लाभ आसानी से मिल रहा है। प्रशासनिक संकल्प से बदली तस्वीर-नक्सलवाद के कारण थमा हुआ विकास अब वनाधिकार पट्ट समर्थन मूल्य में धान खरीदी और पीएम आवास जैसी योजनाओं के माध्यम से धरातल पर दिखाई दे रहा है।

थाना अनंतपुर पुलिस द्वारा ग्राम मालगांव के वार्षिक मेला में खुडखुडिया खेलाते 2 आरोपी को किया गया गिरफ्तार

कोण्डागांव। पुलिस अधीक्षक कोण्डागांव त्रिलोक बंसल के द्वारा जिले का कार्य भार ग्रहण करने के पश्चात् थाना क्षेत्र में चल रहे अवैध कार्यों पर रोक लगाने एवं प्रभावी कार्यवाही करने दिशा निर्देश दिये हैं।

इसी तारतम्य में 7 अप्रैल को पेट्रोलिंग दौरान जरिये मुखबीर सूचना मिला कि कुछ लोग ग्राम मालगांव मेला स्थल टेकरी के पास खुडखुडिया नामक जुआ में रूपया पैसा का दांव लगाकर जुआ खेल एवं खेला रहे है कि सुचना पर ग्राम मालगांव मेला स्थल टेकरी पास पहुँचकर बताये स्थान पर घेराबंदी कार्यवाही कर दो व्यक्ति को खुडखुडिया नामक जुआ खेलाते पकड़े आरोपियों का नाम पता पूछने पर अपना नाम अरविंद नेताम पिता आलेख नेताम उम्र 30 वर्ष जाति मुरिया निवासी मालगांव थाना अनंतपुर जिला कोण्डागांव, नीलू सोरी सुकालु राम सोरी उम्र 24 वर्ष जाति मुरिया निवासी मालगांव थाना अनंतपुर जिला कोण्डागांव का रहने वाले बताये उनके पास से 06 नग खुडखुडिया गोटा, 01 नग झण्डा मुण्डा चार्ट, 01 नग टोकनी, 01 प्लास्टिक चटाई, फड से 970/रू. दोनों का तलाशी लेने पर अरविंद नेताम के पास से 200/- रूपये कुल-1170/रू. बरामद किया गया। आरोपियों का कृत्य अपराध धारा सदर का पाये जाने से अपराध क्रमांक 12/2026 छग जुआ प्रतिषेध अधिनियम की धारा 03 के तहत मौके पर विधिवत् कार्यवाही किया गया। सम्पूर्ण कार्यवाही में प्र.आर. 236 भूपेन्द्र मरकाम, प्र.आर. 196 छबीलाल कोर्राम, प्र.आर. 349 श्यामसिंह मरकाम एवं समस्त स्टॉफ का विशेष योगदान रहा।

बस्तर में मानसिक स्वास्थ्य हेतु अंतर-विभागीय दृष्टिकोण की आवश्यकता पर हुई कार्यशाला

जगदलपुर। कलेक्टोरेट में मानसिक स्वास्थ्य और मनो सामाजिक कल्याण पर कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें जिले के विभिन्न विभागों के लगभग 40 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। यह सत्र मनो बस्तर पहल के अंतर्गत जिला प्रशासन और मरीवाला हेल्थ इनिशिएटिव के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया गया, जिसका उद्देश्य बस्तर जिले के आवासीय संस्थानों में रहने वाले जनजातीय बच्चों के लिए मानसिक स्वास्थ्य समर्थन और आत्महत्या रोकथाम के लिए संस्थागत तैयारियों को मजबूत करना था। कार्यशाला का संचालन डॉ. अचल भगत ने किया, जिन्होंने मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण पर एक समग्र (इंटरसेक्शनल) दृष्टिकोण प्रस्तुत किया।

बैंक ऑफ बड़ौदा कोण्डागांव में नेशनल लोक अदालत एवं विधिक साक्षरता शिविर का हुआ आयोजन

कोण्डागांव। आम नागरिकों के प्रति विधिक जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से आज बैंक ऑफ बड़ौदा कोण्डागांव परिसर में 09 मई 2026 एवं विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर का उद्देश्य लोगों को उनके कानूनी अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति जागरूक करना तथा उन्हें निःशुल्क विधिक सहायता की जानकारी एवं आम नागरिकों को नेशनल लोक अदालत के माध्यम से सुलभ, त्वरित एवं सस्ती न्याय व्यवस्था की जानकारी प्रदान करना रहा। इस दौरान प्रतिधारक अधिवक्ता सुरेन्द्र भट्ट के द्वारा विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों जैसे उपभोक्ता अधिकार बैंकिंग से संबंधित कानूनी प्रावधान, साइबर अपराध से बचाव, महिला एवं बाल अधिकार तथा निःशुल्क विधिक सहायता योजनाओं के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित नागरिकों की समस्याओं को सुना गया तथा उन्हें कानूनी सलाह प्रदान की गई। साथ ही लोगों को यह भी बताया गया कि वे किस प्रकार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त कर सकते है। इसी प्रकार नेशनल लोक अदालत के बारे में प्रकाश डालते हुए बताया गया कि इसके माध्यम से आपसी सहमति से मामलों का त्वरित एवं सरल निराकरण किया जा सकता है, जिससे समय व धन दोनो की बचत होती है। विशेष रूप से बैंकिंग एवं ऋण संबंधी प्रकरणों के निपटारे के लिए नेशनल लोक अदालत एक प्रभावी माध्यम है।

हर्राकोडेर मढ़ई-मेला में शमिल हुए चित्रकोट विधायक, आश्रम शाला का किया निरीक्षण

जगदलपुर। बस्तर जिले के चित्रकोट विधानसभा क्षेत्र के अंतिम एवं सुदूर ग्राम पंचायत हर्राकोडेर में मंगलवार को आयोजित पारंपरिक मढ़ई मेला कार्यक्रम में चित्रकोट विधायक विनायक गोयल ने सहभागिता कर उन्होंने श्रद्धापूर्वक मां गंगादेई की पूजा-अर्चना कर क्षेत्र की सुख-समृद्धि और शांति की कामना की। मढ़ई मेला क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है, जिसमें बड़ी संख्या में ग्रामीण, जनप्रतिनिधि और श्रद्धालु शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान विधायक गोयल ने स्थानीय लोगों से संवाद कर उनकी समस्याएं सुनीं और सुझावों पर सकारात्मक पहल का आश्वासन दिया।

उन्होंने कहा कि ऐसे पारंपरिक आयोजन समाज में एकता और भाईचारे को मजबूत करते हैं तथा हमारी संस्कृति को जीवंत बनाए रखते हैं। उन्होने कहा कि जनता का विश्वास ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है, जो उन्हें निरंतर जनसेवा के लिए प्रेरित करता है।

महिलाओं एवं बच्चों के विरुद्ध घटित अपराधों में कोंडागांव पुलिस द्वारा लगातार की जा रही हैं त्वरित एवं कड़ी कार्यवाही

कोण्डागांव। नाबालिक पीड़िता के पिता द्वारा थाना में रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि आरोपी आनंद मंडावी द्वारा 01 अप्रैल 2026 मेला देखने जाने के दौरान उसकी पुत्री नाबालिक पीड़िता को उसके नाबालिक होना जानते हुए बहला फुसलाकर शादी का झांसा देकर उसे अपने साथ अलग-अलग स्थानों पर ले गया और नाबालिक पीड़िता को तुम्हें पसंद करता हूं और तुमसे शादी करना चाहता हूं कह कर नाबालिक पीड़िता के साथ जबरदस्ती यौन संबंध बनाकर बलात्कार किया गया कि नाबालिक पीड़िता के पिता के रिपोर्ट पर थाना फरसगांव में अपराध क्रमांक 39 /2026 धारा 65(1),351(3) बीएनएस 4,6 पोक्सो एक्ट पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। मामले की गंभीरता एवं संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक कोंडागांव त्रिलोक बंसल के निर्देशानुसार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कोंडागांव कपिल चंद्रा के मार्गदर्शन एवं उप पुलिस अधीक्षक अभिनव उपाध्याय एसडीओपी फरसगांव के कुशल पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी फरसगांव निरीक्षक चंद्रशेखर श्रीवास के हमराह टीम गठित कर चंद घंटे के अंदर आरोपी को विधिवत गिरफ्तार किया गया जिसे विधिवत कार्यवाही पश्चात न्यायिक रिमांड हेतु न्यायालय में पेश किया गया। 'प्रमुख योगदान' - निरीक्षक-चंद्रशेखर श्रीवास, उप निरीक्षक- शशि भूषण पटेल, सहा उप निरी.-सुमित्रा सेठिया, महिला प्रधान आर.-जयश्री ध्रुव, आर.-प्रेमलाल मरकाम, कृष्णा सेठिया महिला आर.-कौशल्या सोरी।

लाल आतंक के सूर्यास्त के साथ सुकमा में उदय हुआ स्वास्थ्य सेवाओं का सूरज

जगदलपुर। बस्तर के सुदूर अंचलों में कभी लाल आतंक की धमक से सहमे रहने वाले सुकमा जिले की तस्वीर अब पूरी तरह बदल चुकी है। दशकों पुराने संघर्ष और भय के बादलों को चीरकर अब यहाँ विकास और खुशहाली की नई किरणें बिखर रही है। जिला प्रशासन सुकमा और बेंगलुरु के एनटीआर फाउंडेशन के साझा प्रयासों से आयोजित दो दिवसीय सुपर स्पेशलिटी मेगा स्वास्थ्य शिविर इस बात का जीवंत प्रमाण है कि अब सुकमा नक्सलवाद की बेड़ियों को तोड़कर स्वस्थ और सशक्त होने की राह पर निकल पड़ा है। मिनी स्टेडियम में विगत 28 और 29 मार्च को आयोजित इस शिविर ने यह स्पष्ट संदेश दिया कि जहाँ कभी गोलियों की गूँज थी, आज वहाँ सेवा और संकल्प के गीत गाए जा रहे हैं। लाल आतंक की समाप्ति के इस दौर में जब क्षेत्र में शांति और सुरक्षा का माहौल बना है, तब प्रशासन की पहुँच अंतिम छोर के व्यक्ति तक आसान हुई है। प्रदेश के वन मंत्री एवं सुकमा जिले के प्रभारी मंत्री केदार कश्यप के द्वारा शुभारंभ पश्चात इस मेगा स्वास्थ्य शिविर में उन संवेदनशील और अंदरूनी क्षेत्रों के 3,700 से अधिक ग्रामीण बेखौफ होकर पहुँचे, जो कभी मुख्यधारा से कटे हुए थे। कमिश्नर बस्तर ज्ञेमन सिंह के निर्देशानुसार कलेक्टर अमित कुमार के मार्गदर्शन में आयोजित उक्त मेगा स्वास्थ्य शिविर में कुल 6,500 से अधिक लाभार्थियों की उपस्थिति ने यह साबित कर दिया कि अब ग्रामीण बंदूकों के साये से निकलकर आधुनिक चिकित्सा और विशेषज्ञ परामर्श पर भरोसा जता रहे हैं। शिविर के दौरान 21 विशेषज्ञ डॉक्टरों और 40 स्वास्थ्य योद्धाओं की टीम ने इन वनवासियों के लिए देवदूत बनकर काम किया।

संक्षिप्त समाचार

बिलासपुर गनियारी जन स्वास्थ्य केंद्र पहुची अंजलि तेंदुलकर, सारा तेंदुलकर, सानिया चांडोक, स्वास्थ्य सेवाओं का लिया जायजा, गांव की चौपाल से अस्पताल तक चर्चा

बिलासपुर । विश्व प्रसिद्ध क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर का परिवार मंगलवार को बिलासपुर पहुंचा अंजलि तेंदुलकर, सारा तेंदुलकर और सानिया चांडोक तीनों सीधे मंगला चौक स्थित कोर्टयार्ड मैरियट में ठहरीं, जहां उनका 24 घंटे का प्रवास पर गनियारी स्थित जन स्वास्थ्य केंद्र पहुंचीं। यहां स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति का जायजा लिया गया, फुलवारी केंद्र का निरीक्षण किया गया और डॉक्टरों के साथ बैठक कर व्यवस्थाओं पर चर्चा हुई। सूत्रों के मुताबिक यह पूरा दौरा एक सामाजिक संस्था के आमंत्रण से जुड़ा रहा और स्वास्थ्य क्षेत्र में संभावित सहयोग को लेकर भी बातचीत हुई। खबर लिखे जाने तक सचिन तेंदुलकर परिवार अंजलि तेंदुलकर, सारा तेंदुलकर और सानिया चांडोक गनियारी स्थित जन स्वास्थ्य केंद्र परिसर में मौजूद रहीं द्य मिली जानकारी के अनुसार आज ही कार्यक्रम समाप्त करने के बाद परिवार आज शाम बिलासपुर से मुंबई के लिए रवाना हो सकते है।

मजदूर की शिकायत पर इंटक अध्यक्ष इदरीस अंसारी ने कराया समझौता, 70 हजार के विवाद का हुआ निपटारा

गौरेला-पेंड्रा-मरवाही। जिले में मजदूरी भुगतान को लेकर हुए विवाद में राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस (इंटक) के जिला अध्यक्ष इदरीस अंसारी की पहल पर आपसी समझौता कर मामला सुलझा लिया गया। मामला सारबहरा सिंचाई नगर का है, जहां लेबर ठेकेदार नरेंद्र सिंह सतनामी की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए दोनों पक्षों के बीच सहमति बनाई गई। जानकारी के अनुसार, पूर्व सरपंच मुन्ना सिंह भैना (अंजनी) द्वारा निर्माण कार्य कराया गया था, जिसकी मजदूरी करीब 70 हजार रुपये का भुगतान लंबित था। इस संबंध में लेबर ठेकेदार नरेंद्र सिंह सतनामी ने थाना गौरेला में शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस द्वारा प्रारंभिक कार्रवाई करते हुए मामला न्यायालय भेज दिया गया था। इसी दौरान नरेंद्र सिंह का दुर्घटना हो जाने के कारण लंबे समय तक उनका इलाज चलता रहा, जिससे वे आर्थिक रूप से कमजोर हो गए। ठीक होने के बाद जब मजदूरी के भुगतान के लिए दबाव बढ़ा, तो वे न्यायालय जाने में असमर्थ रहे और अपनी समस्या लेकर इंटक कार्यालय पहुंचे। मामले की गंभीरता को देखते हुए इंटक अध्यक्ष इदरीस अंसारी ने दोनों पक्षों को बुलाकर चर्चा की। मुन्ना सिंह भैना ने अपनी खराब तबीयत और लंबे इलाज का हवाला देते हुए तत्काल भुगतान में असमर्थता जताई। इसके बाद इदरीस अंसारी ने मध्यस्थता करते हुए 70 हजार रुपये की जगह 45 हजार रुपये में समझौता कराया। यह राशि तीन किस्तों में देने पर दोनों पक्षों के बीच लिखित सहमति बनी। हालांकि, शुरुआत में नरेंद्र सिंह ने पूरे भुगतान की मांग की।

जल संरक्षण और 'नवा तरिया' पर जोर, पंचायतवार की समीक्षा

30 अप्रैल तक सभी अपूर्ण आवास पूर्ण करें-कलेक्टर संजय अग्रवाल

- आवास निर्माण में तेजी लाने के निर्देश, कोटा जनपद पर जताई नाराजगी
- पीएम आवास के 25 हजार से अधिक घर प्रगतिरत, 30 अप्रैल तक पूरा करने का लक्ष्य

बिलासपुर। जिले में संचालित आवास एवं मनरेगा कार्यों की प्रगति को लेकर कलेक्टर संजय कुमार अग्रवाल ने सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने 30 अप्रैल तक सभी अपूर्ण आवास पूर्ण करने के निर्देश देते हुए कार्यों में तेजी लाने पर जोर दिया। कलेक्टर श्री संजय कुमार अग्रवाल एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री संदीप कुमार अग्रवाल की अध्यक्षता में आज जिला पंचायत सभाकक्ष में विभिन्न ग्रामीण विकास योजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, उपअभियंता, कार्यक्रम अधिकारी मनरेगा, विकासखंड समन्वयक आवास तथा तकनीकी सहायक उपस्थित रहे। बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण, पीएम-जनमन योजना एवं मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अपूर्ण आवासों को निर्धारित समयसीमा में पूर्ण कराने के निर्देश दिए गए। जिले में वित्तीय वर्ष 2024-26 के अंतर्गत स्वीकृत 71,508 आवासों में से 45,889 आवास पूर्ण हो चुके हैं, जबकि 25,619 आवास प्रगतिरत हैं। कलेक्टर ने सभी तकनीकी सहायकों को 30 अप्रैल 2026 तक शेष आवासों को पूर्ण कराने का लक्ष्य दिया। पीएम-जनमन योजना में अपेक्षित प्रगति नहीं होने पर कलेक्टर ने जनपद पंचायत कोटा के प्रति नाराजगी व्यक्त करते हुए संबंधित अधिकारियों को चेतावनी दी और शीघ्र प्रगति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही प्रत्येक आवास में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम स्थापित करने हेतु हितग्राहियों को प्रेरित करने के निर्देश भी दिए गए। कलेक्टर ने मनरेगा अंतर्गत चल रहे कार्यों की विकासखंडवार एवं पंचायतवार समीक्षा करते हुए निर्देशित किया कि सभी अपूर्ण कार्यों को प्राथमिकता से पूर्ण किया जाए। प्लिंथ स्तर के आवासों एवं शेष निर्माणाधीन कार्यों में 90 दिवस का रोजगार उपलब्ध कराकर कार्य पूर्ण करने को कहा गया।उन्होंने जल संरक्षण को प्राथमिकता देते हुए नवा तरिया आय के जरिया योजना के तहत नए तालाबों के चयन, स्वीकृति एवं शीघ्र पूर्णता के निर्देश दिए। साथ ही युक्तधारा पोर्टल के अनुसार कार्यों के चयन एवं क्रियान्वयन सुनिश्चित करने को कहा गया। स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत व्यक्तिगत एवं सामुदायिक शौचालय तथा ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के अपूर्ण कार्यों को अप्रैल माह के अंत तक पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। इसके अतिरिक्त जिला विकास प्राधिकरण योजना के तहत लंबित एवं अप्रारंभ कार्यों को भी 30 अप्रैल 2026 तक पूरा करने के निर्देश दिए गए।

अखिल भारतीय रेल क्रिकेट प्रतियोगिता में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की टीम उपविजेता

बिलासपुर। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की क्रिकेट टीम ने अखिल भारतीय रेल क्रिकेट प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए उपविजेता का गौरव प्राप्त किया। फाइनल मुकाबले में टीम ने मेट्रो रेलवे के विरुद्ध शानदार संघर्ष का परिचय दिया और द्वितीय स्थान प्राप्त करते हुए रजत पदक अपने नाम किया। इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता का लीग चरण चेन्नई में तथा नॉकआउट चरण मुंबई में आयोजित किया गया, जिसमें देशभर की विभिन्न रेलवे टीमों ने भाग लिया। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की टीम ने पूरे टूर्नामेंट में लगातार उत्कृष्ट खेल का प्रदर्शन करते हुए फाइनल तक का प्रभावशाली सफर तय किया। उल्लेखनीय है कि दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की क्रिकेट टीम ने पिछले चार वर्षों में तीन बार फाइनल में स्थान बनाकर पदक सुनिश्चित किया है, जिसमें एक स्वर्ण पदक एवं दो रजत पदक शामिल हैं। यह उपलब्धि खिलाड़ियों की निरंतर मेहनत, अनुशासन एवं उत्कृष्ट खेल भावना को दर्शाती है। इस गौरवपूर्ण उपलब्धि के उपरांत आज टीम के खिलाड़ियों ने महाप्रबंधक श्री तरुण प्रकाश से शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर महाप्रबंधक श्री तरुण प्रकाश ने खिलाड़ियों को कहा कि टीम ने जिस समर्पण, अनुशासन और खेल भावना के साथ प्रदर्शन किया है, वह अत्यंत सराहनीय है। यह उपलब्धि न केवल दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बल्कि पूरे भारतीय रेल के लिए गर्व का विषय है। मुझे विश्वास है कि आप सभी भविष्य में भी इसी प्रकार उत्कृष्ट प्रदर्शन कर नए कीर्तिमान स्थापित करेंगे। उन्होंने सभी खिलाड़ियों एवं प्रशिक्षकों को हार्दिक बधाई देते हुए उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएँ दीं। साथ ही दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे खेल संघ के अध्यक्ष, महासचिव, संयुक्त महासचिव एवं समस्त खेल परिवार द्वारा भी टीम के सभी खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों को इस उपलब्धि पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ दी गईं।

आमागोहन पटवारी अंकित स्वर्णकार को हटाने ग्रामीणों ने घेरा कलेक्ट्रेट

- कोटा विधायक अटल श्रीवास्तव भी ग्रामीणों के साथ पहुचें, पूर्व के शिकायत पर कार्यवाही नहीं

बिलासपुर। बिलासपुर जिला के कोटा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम आमागोहन मोहली एवं तुलुफके ग्रामीण हल्का मे पदस्थ पटवारी अंकित स्वर्णकार के विरूध्द शिकायत एवं स्थानांतरण करने की मांग लेकर कलेक्टर कार्यालय बिलासपुर पहुचें ग्रामीण भारी संख्या में कोटा विधायक अटल श्रीवास्तव के निवास पहुचे फिर विधायक के साथ कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर कलेक्टर महोदय से पटवारी अंकित स्वर्णकार के विरूध्द शिकायत दर्ज कराया ग्रामीणो ने कलेक्टर महोदय से चर्चा के दौरान बताया कि पटवारी पिछले 6 माह से लगातार मनमानी कर किसानों से दुर्व्यव्हार के साथ आर्थिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहा है फौती नामांतरण बटवारा सीमांकन जाति निवास सहित प्रत्येक कार्य के लिये खुलेआम मोटी रकम का मांग करता है धान के गिरदावरी भौतिक सत्यापन के नाम पर किसानों से हजारो राशि का मांग किया गया अनेक किसानों द्वारा राशि नही देने पर 150 किसानों का धान का रकबा विलोपित या कम या त्रुटि कर धान बिक्री करने से जानबुझकर वोंचित किया गया वही अन्य साहुकार जो धान का फसल नही बोये है उनका अवैध पंजीयन कर गलत लोगों का धान बिक्री करने मे फायदा पहुचाया गया है ग्राम के शासकीय भूमि से मिटटी निकालकर ठेकेदारों को लाखों में बेचा जा रहा है ग्रामीणों ने बताया कि पटवारी के उक्त कारनामों की शिकायत तहसीलदार एवं एसडीएम से अनेक बार की गई है।

जिले में जनसमस्या निवारण शिविरों की तिथियां तय,16 अप्रैल से शुरुआत होगी

बिलासपुर। जिले में आम नागरिकों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए जनसमस्या निवारण शिविरों का कैलेंडर जारी कर दिया गया है। कलेक्टर संजय अग्रवाल के निर्देशानुसार ये शिविर 16 अप्रैल से प्रारंभ होकर 2 जुलाई 2026 तक विभिन्न तहसीलों में आयोजित किए जाएंगे। शिविरों में प्राप्त आवेदनों का मौके पर निराकरण करने पर विशेष जोर रहेगा। जारी कार्यक्रम के अनुसार 16 अप्रैल को बिल्हा से शिविरों की शुरुआत होगी। इसके बाद 25 अप्रैल को बिलासपुर और 30 अप्रैल को तखतपुर में शिविर आयोजित किए जाएंगे। मई माह में 8 मई को मस्तूरी, 16 मई को कोटा, 22 मई को बेलतरा तथा 28 मई को सकरी में शिविर लगाए जाएंगे। इसी क्रम में जून माह में 4 जून को बेलगहना, 12 जून को रतनपुर, 20 जून को पचपेड़ी और 25 जून को सीपत में शिविर आयोजित होंगे। अंतिम चरण में 2 जुलाई को बोदरी में शिविर आयोजित कर अभियान का समापन किया जाएगा। कलेक्टर ने सभी जिला स्तरीय अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि वे निर्धारित तिथियों पर शिविरों में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहें तथा प्राप्त शिकायतों का समय-सीमा में निराकरण सुनिश्चित करें। साथ ही, ग्रामीण क्षेत्रों में शिविरों का व्यापक प्रचार-प्रसार कर अधिक से अधिक लोगों को लाभ पहुंचाने के निर्देश एसडीओ राजस्व और सीईओ जनपद को दिए गए।

143 नए लोको,2,263 किलोवाट सौर ऊर्जा और एआई ड्रोन के साथ रची प्रगति की नई गाथा.....

ऊर्जा, नवाचार और हरित पहल से सशक्त दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे!

बिलासपुर। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, जो देश के माल परिवहन की धुरी के रूप में अपनी विशिष्ट पहचान रखता है, निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर है। इस सशक्त व्यवस्था को ऊर्जा प्रदान करने में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के विद्युत विभाग की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। वित्तीय वर्ष 2025ङ्क26 के दौरान विभाग ने रिकॉर्ड उपलब्धियाँ हासिल करते हुए हरित ऊर्जा, अत्याधुनिक तकनीक और परिचालन दक्षता के क्षेत्र में नए मानक स्थापित किए हैं, जिससे दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की कार्यक्षमता और विश्वसनीयता और अधिक सुदृढ़ हुई है। वित्तीय वर्ष 2025-26 की प्रमुख उपलब्धि के रूप में 143 नए विद्युत लोकोमोटिव का सफल कमीशनिंग किया गया, जिनमें 74 इलेक्ट्रिक लोको शेड/भिलाई तथा 69 इलेक्ट्रिक लोको शेड/बिलासपुर में शामिल हैं। यह एक वित्तीय वर्ष में अब तक की सर्वाधिक उपलब्धि है। इसके साथ ही कुल लोकोमोटिव बेड़े की संख्या 721 से बढ़कर 805 हो गई, जो 11.65ब्र की उल्लेखनीय वृद्धि दर्शाती है। मालगाड़ियों के लिए औसत मासिक लोको उपलब्धता 665.02 रही, जो रेलवे बोर्ड के निर्धारित लक्ष्य 651 से अधिक है। हरित ऊर्जा को बढ़ावा देते हुए प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के अंतर्गत 2,263.625 किलोवाट पीक क्षमता के सौर संयंत्र की स्थापना कर चालू किए गए, जिससे रेलवे परिसंपत्तियों को स्वच्छ ऊर्जा उपलब्ध कराई जा रही है तथा कार्बन उत्सर्जन में कमी लाई जा रही है। तकनीकी नवाचार के क्षेत्र में रायपुर मंडल ने भारतीय रेल में पहली बार एआई-सक्षम ड्रोन के माध्यम से ओवरहेड उपकरण (ओएचई) की निगरानी शुरू की है। यह अत्याधुनिक प्रणाली हाई वोल्टेज तारों का सुरक्षित एवं सटीक निरीक्षण कर संभावित खामियों की पहचान करती है, जिससे कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित होती है। विद्युत अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण हेतु 211.45 ट्रैक किलोमीटर निक्को संपर्क तार एवं 173.44 ट्रैक किलोमीटर एल्युमिनियम कैटेनरी तार का प्रतिस्थापन किया गया। इसके अतिरिक्त सिग्नलिंग प्रणाली की विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए 44 नए ऑटो-ट्रांसफॉर्मर भी स्थापित किए गए।

खाद्य आयोग के अध्यक्ष संदीप ने उचित मुल्य दुकानों आंगनबाड़ी केन्द्र और छात्रावास का किया निरीक्षण....

गौरेला पेंड्रा मरवाही। छत्तीसगढ राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष संदीप शर्मा ने आज जिला प्रवास के दौरान विभिन्न उचित मूल्य दुकानों और आंगनबाड़ी केन्द्र एवं छात्रावास का निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद परियोजना कार्यालय एकीकृत आदिवासी विकास विभाग के सभा कक्ष में बैठक लेकर सार्वजनिक वितरण प्रणाली, पूरक पोषण आहार एवं मध्यान भोजन योजना तथा शासकीय आश्रम-छात्रावास को बीपीएल दर पर प्रदाय खाद्यान्न भोजन की समीक्षा की। उन्होंने जिले के सभी शासकीय उचित मूल्य दुकानों को समय पर खोले जाने, नागरिक आपूर्ती निगम के परिवहनकर्ताओं द्वारा हर महीने समय पर खाद्यान्न भंडारण और तौलकर खाद्यान्न वितरण के निर्देश दिए। उन्होंने राज्य शासन के निर्देश अनुसार सभी राशन दुकानों में तीन माह के खाद्यान्न भंडारण 20 अप्रैल तक करने और प्रत्येकहितग्राही को अनिवार्य रूप से अप्रैल, मई एवं जून तीन माह का चावल एकमुश्त बांटने के निर्देश दिए। बैठक में पूरक पोषण आहार योजना के संदर्भ में पोषण ट्रेकर में दर्ज एवं दैनिक उपस्थिति का पंजीकृत बच्चों की संख्या तथा भौतिक रूप से उपस्थित बच्चों की संख्या से प्रति परीक्षण करने हेतु केंद्रों का औचक निरीक्षण करने और आंगनबाडी केन्द्रो में सभी सूचनाओं के प्रदर्शन के निर्देश दिए गए। इसी तरह जिले के सभी स्कूलों में मध्यान्ह भोजन के अंतर्गत प्रति डाईट खाद्यान्न दाल, सब्जी आदि की मात्रा प्रदर्शित करने तथा इसके क्रियान्वयन के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि सभी शासकीय आश्रम-छात्रावास में दोनों समय भोजन में दाल प्रदाय किया जाए, प्रति डाइट खाद्यान्न, दाल, खाद्य तेल, सब्जी की निर्धारित मात्रा को भोजन कक्ष में प्रदर्शित और क्रियान्वित किया जाए। बैठक में खाद्य आयोग के सदस्य सचिव श्री राजीव कुमार जायसवाल, जिला पंचायत सीईओ श्री मुकेश रावटे, खाद्य अधिकारी श्रीमती स्वेता अग्रवाल सहित सहायक आयुक्त आदिवासी विकास, जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एंव बाल विकास, जिला शिक्षा अधिकारी, जिला प्रबंधक नान तथा जिले के समस्त सहायक खाद्य अधिकारी एवं खाद्य निरीक्षक उपस्थित थे।समीक्षा बैठक के पूर्व राज्य खाद्य आयोग के दल द्वारा विभिन्न राशन दुकानों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान ग्राम पंचायत बसंतपुर, धोबहर एवं निमधा की शासकीय उचित मूल्य दुकान बंद पाई गई, जिस पर आयोग के अध्यक्ष द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए दुकान बंद रखने वाले संचालकों के विरुद्ध तत्काल कार्यवाही के निर्देश दिए। उन्होंने ग्राम पंचायत धोबहर की निलंबित दुकान को संलग्न संस्था से तत्काल प्रारंभ कराने के निर्देश दिए। ग्राम पंचायत नरौर में निरीक्षण के दौरान तीन माह का शेष चावल का शीघ्र भंडारण पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। दल द्वारा आंगनबाडी केन्द्र और एकलव्य छात्रावास डोंगरिया का निरीक्षण कर बच्चों को दी जाने वाली भोजन गुणवत्ता की जांच की। दल द्वारा पेंड्रा स्थित आदिम जाति बालिका छात्रावास का निरीक्षण किया गया तथा छात्रावास के छात्रों को दोनों समय के भोजन में दाल प्रदाय करने के निर्देश दिए। आयोग के अध्यक्ष ने खाद्यान से संबंधित शिकायतों के लिए खाद्य विभाग द्वारा स्थापित राज्य स्तरीय कॉल सेंटर की नम्बर छात्रावासों में प्रदर्शित करने के निर्देश खाद्य अधिकारी को दिए।

बालको की पहल से मूंगफली बनी किसानों की आय बढ़ाने का सशक्त माध्यम

कोरबा। कोरबा के आसपास के ग्रामीण इलाकों में खेती का तरीका धीरे-धीरे बदल रहा है। पहले किसान ज्यादा पानी वाली धान की खेती पर निर्भर थे, लेकिन अब वे मूंगफली की खेती की ओर बढ़ रहे हैं। भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड (बालको) अपनी 'मोर जल मोर माटी' योजना के जरिए 40 गांवों के 9,000 से अधिक किसानों को सहयोग दे रही है। परियोजना के तहत जल प्रबंधन, आधुनिक खेतों, पशुपालन, गैर-लकड़ी वन उत्पाद और किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसी क्रम में बालको ने क्षेत्र के किसानों के बीच मूंगफली की खेती को एक लाभकारी विकल्प के रूप में प्रोत्साहित किया है। पहले क्षेत्र में बहुत कम किसान मूंगफली की खेती करते थे, वह भी केवल घरेलू उपयोग के लिए। पारंपरिक तरीकों के कारण लागत अधिक और उत्पादन कम होने से किसानों को पर्याप्त लाभ नहीं मिल पाता था। साथ ही बाजार तक पहुंच की कमी भी एक बड़ी समस्या थी। बालको ने बेहतर बीज, खाद और तकनीकी मदद देकर इन समस्याओं को कम किया है। अब किसानों को लाइन से बुवाई, बीज उपचार और सही मात्रा में खाद देने जैसे तरीकों की ट्रेनिंग दी जा रही है, जिससे उत्पादन बढ़ा है। कंपनी के सामुदायिक विकास प्रयासों का असर साफदिखाई दे रहा है। पहले जहां 50 से भी कम किसान मूंगफली उगाते थे।

पार्लर जैसा निखार अब घर बैठे करें

गर्मियों का मौसम जैसे ही आता है हमें स्किन से जुड़ी कई तरह की प्रॉब्लम्स से जूझना पड़ जाता है। तेज धूप, लगातार बहता पसीना और धूल-मिट्टी की वजह से स्किन बुरी तरकी से टैन और डैमेज हो जाती है। जब ऐसा होता है तो हम महंगे ट्रीटमेंट्स और प्रोडक्ट्स की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। लेकिन हर बार यह पॉसिबल भी नहीं होता कि आप पार्लर जाएं और इतने पैसे खर्च कर सकें। आज घर पर ही बने कुछ आसान और नेचुरल फ्रूट फेशियल्स के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें अपनाकर आप अपनी स्किन को ग्लोइंग और हाइड्रेटेड बनाकर रख सकेंगे।

ग्लोइंग स्किन के लिए पपीते का फेशियल

आपकी स्किन के लिए पपीते को काफी ज्यादा फायदेमंद माना जाता है। इसमें कुछ एंजाइम्स पाए जाते हैं जो आपकी स्किन से डेड सेल्स को हटाकर उसे ग्लोइंग बना देते हैं। इसके लिए आपको एक पके हुए पपीते को अच्छे से मैश कर लेना है और इसे अपने पूरे चेहरे पर लगा लेना है। 20 मिनट के लिए छोड़ दें और फिर फ्रेश पानी से चेहरे को अच्छी तरह से धो लें। रेगुलर इसके इस्तेमाल से आपकी स्किन सॉफ्ट और क्लियर बनती है।

ठंडक और हाइड्रेशन के लिए तरबूज का फेशियल

तरबूज की खासियत होती है कि उसमें पानी की मात्रा काफी ज्यादा होती है। ऐसे में इसका इस्तेमाल स्किन को अंदर से हाइड्रेटेड रखने के लिए आपको जरूर करना चाहिए। इसके लिए आपको सबसे पहले तरबूज का रस निकाल लेना है और फिर उसमें थोड़ा सा शहद मिला लेना है। अब इसे अपने पूरे चेहरे पर लगा लें। जब आप इसका इस्तेमाल अपने चेहरे पर करेंगे तो आपकी स्किन को ठंडक मिलेगा और साथ ही मॉइस्चर भी बरकरार रहेगा।

हिंदू कैलेंडर के अनुसार वैसाख माह की शुरुआत के साथ ही कई महत्वपूर्ण व्रत और त्योहार मनाए जाते हैं। इन्हीं में से एक है मासिक कृष्ण जन्माष्टमी, जो हर महीने कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाई जाती है। यह दिन भगवान श्रीकृष्ण की भक्ति और पूजा के लिए बेहद खास माना जाता है।

कब है मासिक कृष्ण जन्माष्टमी?

अप्रैल 2026 में मासिक कृष्ण जन्माष्टमी की तिथि इस प्रकार है:
अष्टमी तिथि प्रारंभ: 9 अप्रैल 2026, रात 09:19 बजे
अष्टमी तिथि समाप्त: 10 अप्रैल 2026, रात 11:15 बजे

पूजा का शुभ मुहूर्त

10 अप्रैल को दोपहर 12:00 बजे से 12:45 बजे तक
इस समय भगवान श्रीकृष्ण की पूजा, आरती और मंत्र जाप करना अत्यंत फलदायी माना जाता है।

मासिक कृष्ण जन्माष्टमी पर भगवान श्रीकृष्ण की पूजा-अर्चना

मासिक कृष्ण जन्माष्टमी का महत्व

मासिक कृष्ण जन्माष्टमी हर महीने भगवान श्रीकृष्ण के जन्म की स्मृति में मनाई जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भाद्रपद मास की कृष्ण अष्टमी को श्रीकृष्ण का जन्म हुआ था, इसलिए हर माह इस तिथि पर उनका स्मरण किया जाता है। इस दिन व्रत रखने और विधि-विधान से पूजा करने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। खासतौर पर संतान सुख की इच्छा रखने वाले लोग इस दिन व्रत और पूजा करते हैं।

पूजा में करें इन मंत्रों का जाप

इस दिन श्रीकृष्ण की कृपा पाने के लिए इन मंत्रों का जाप करना शुभ माना जाता है:

ॐ कृष्णाय नमः
हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे
ॐ श्री कृष्णः शरणं ममः
ॐ देवकीनन्दनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात
ॐ नमो भगवते तस्मै कृष्णाय कुण्ठमेधसे

भगवान श्रीकृष्ण की पूजा क्यों है खास?

भगवान श्रीकृष्ण को प्रेम, भक्ति, धर्म और सत्य का प्रतीक माना जाता है। उनका जीवन हमें सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। मासिक जन्माष्टमी पर उनकी पूजा करने से मानसिक शांति मिलती है और जीवन में सकारात्मकता आती है।

गर्मियों में स्टाइलिश लुक के लिए ब्लाउज डिजाइन चुनें

गर्मियों का मौसम आते ही फैशन में हल्के और आरामदायक कपड़ों की मांग बढ़ जाती है, खासकर साड़ी के साथ पहने जाने वाले ब्लाउज में। समर स्पेशल ब्लाउज डिजाइन ऐसे होते हैं जो आपको स्टाइलिश दिखाने के साथ-साथ ठंडक का एहसास भी देते हैं। इस मौसम में कॉटन, लिनन और सॉफ्ट फैब्रिक से बने ब्लाउज सबसे ज्यादा पसंद किए जाते हैं। स्लीवलेस, बैकलेस, डीप नेक और लूज फिट डिजाइन न केवल ट्रेंड में हैं बल्कि पहनने में भी बेहद कंफर्टेबल होते हैं। सही ब्लाउज डिजाइन आपके पूरे लुक को आकर्षक और खास बना सकता है।

स्लीवलेस ब्लाउज

गर्मियों में ब्लाउज चुनते समय सबसे जरूरी होता है फैब्रिक और डिजाइन का सही चुनाव। कॉटन और लिनन जैसे फैब्रिक पसीना सोखते हैं और आपको दिनभर फ्रेश महसूस कराते हैं। ऐसे में स्लीवलेस ब्लाउज डिजाइन सबसे ज्यादा ट्रेंड में रहते हैं। ये न सिर्फ स्टाइलिश दिखते हैं बल्कि गर्मी से राहत भी देते हैं।

हॉल्टर नेक ब्लाउज

हॉल्टर नेक ब्लाउज भी समर सीजन के लिए बेहतरीन ऑप्शन है। यह डिजाइन आपकी नेकलाइन को हाइलाइट करता है और आपको एक मॉडर्न लुक देता है। इसके अलावा बैकलेस ब्लाउज डिजाइन भी काफी पॉपुलर है, जो पार्टी या फंक्शन के लिए परफेक्ट रहते हैं।

बोट नेक ब्लाउज

अगर आप कुछ सिंपल और एलिगेंट चाहती हैं, तो बोट नेक ब्लाउज ट्राय कर सकती हैं। यह ऑफिस या डेली वियर के लिए भी अच्छा ऑप्शन है। वहीं, फ्रंट नॉट या टाई-अप ब्लाउज डिजाइन भी आजकल काफी ट्रेंड में है, जो आपके लुक को स्टाइलिश और यूनिक बनाते हैं।

स्टील शेड्स ब्लाउज

समर में हल्के रंग जैसे पेस्टल शेड्स, व्हाइट, बेबी पिंक और स्काई ब्लू ज्यादा पसंद किए जाते हैं। ये रंग न सिर्फ आंखों को सुकून देते हैं बल्कि आपको कूल और फ्रेश लुक भी देते हैं।

सुबह के लिए एनर्जी ड्रिंक

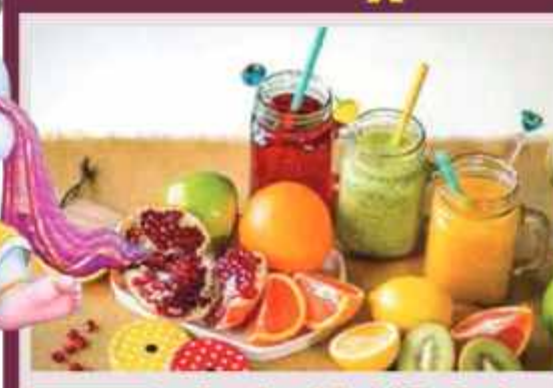

आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में दिन की सही शुरुआत करना बहुत जरूरी है। अगर सुबह शरीर को सही पोषण और ऊर्जा मिल जाए, तो पूरा दिन एक्टिव और फ्रेश महसूस होता है। मॉर्निंग एनर्जी ड्रिंक्स न केवल शरीर को हाइड्रेट करते हैं, बल्कि मेटाबॉलिज्म बढ़ाकर आपको दिनभर के लिए तैयार भी करते हैं। इसलिए हेल्दी ड्रिंक्स को अपनी सुबह की आदत बनाना एक अच्छा विकल्प है।

नींबू-शहद पानी

एक गिलास गुनगुने पानी में आधा नींबू का रस और 1 चम्मच शहद मिलाएं। यह ड्रिंक शरीर को डिटॉक्स करता है, मेटाबॉलिज्म बढ़ाता है और तुरंत एनर्जी देता है। अगर आप सुबह इस ड्रिंक को पीते हैं तो आप दिनभर एनर्जी से भरपूर महसूस करेंगे।

नारियल पानी और चिया सीड्स

एक गिलास नारियल पानी में 1 चम्मच चिया सीड्स डालकर 10 मिनट भिगो दें। यह शरीर को हाइड्रेट करता है और लंबे समय तक ऊर्जा बनाए रखता है। ये आपके वजन को कंट्रोल में रखने में काफी मदद करता है। इसे पीने से आपको दिनभर पानी की कमी महसूस नहीं होगी।

केला और दूध स्मूदी

1 केला, 1 गिलास दूध और थोड़ा शहद ब्लेंड करें। यह प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से भरपूर होता है, जो तुरंत एनर्जी देता है यह स्मूदी आपका नाश्ते का काम करेगी। अगर आप इसे सुबह में पीते है तो इसके बाद आपको कुछ खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

ग्रीन टी और अदरक

ग्रीन टी में थोड़ा कद्दूकस किया हुआ अदरक डालकर उबालें यह शरीर को तरोताजा करता है और फैट बर्न करने में मदद करता है। इसे पीने के बाद कुछ ही दिनों में आपको अपने शरीर में बदलाव देखने को मिलेगा।

सेब और गाजर जूस

1 सेब और 1 गाजर को जूसर में निकालें। आप चाहे तो सी सुबह के नाश्ते के साथ भी ले सकते हैं या फिर इसे नाश्ते से पहले भी पी सकते हैं। यह विटामिन्स से भरपूर होता है और दिनभर के लिए ताजगी देता है।

आज का राशिफल

मेष राशि - आज अपनी सोच पर भरोसा रखें। स्वास्थ्य संबंधी छोटी समस्या को भी नजरअंदाज न करें, वरना यह बड़ी बीमारी बन सकती है। किसी निराशाजनक खबर के कारण अचानक यात्रा करनी पड़ सकती है। व्यापार में भावुक होकर फैसला न लें।

वृषभ राशि - खुशियों से भरा दिन है। मित्रों के साथ पुराने मनमुटाव दूर होंगे। नया वाहन खरीदने की इच्छा आज पूरी हो सकती है। धन में वृद्धि होने से आप परिवार को दिया वादा पूरा कर पाएंगे। नौकरीपेशा लोग अगले दिन की योजना बनाने में व्यस्त रहेंगे।

मिथुन राशि - आज का दिन लाभ लेकर आएगा, लेकिन बजट बनाकर चलना बेहतर होगा। हर काम में रूटीन बनाए रखें। लेन-देन के मामले में स्पष्ट रहें, वरना बड़ा नुकसान हो सकता है। माता-पिता की सेवा में समय बिताएंगे और जीवनसाथी का भरपूर सहयोग मिलेगा।

कर्क राशि - उन्नति का दिन है। रुके हुए काम पूरे होंगे और विभिन्न क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन करेंगे। आय बढ़ने से मन प्रसन्न रहेगा। धार्मिक कार्यों में रुचि जगेगी। नौकरी के साथ नया काम शुरू करने की योजना आज सफल हो सकती है।

सिंह राशि - विशेष फलदायी दिन है। घरेलू मामलों में सावधानी बरतें और विवादों से दूर रहें। संपत्ति का सौदा करने से पहले स्वतंत्र जांच जरूर कर लें। भाई-बहनों के साथ बाहर घूमने की प्लानिंग बनेगी। माता-पिता से अपने मन की बात कह सकते हैं।

कन्या राशि - दिन उलझनों भरा रह सकता है, लेकिन भाईचारा बढ़ाने पर जोर रहेगा। अविवाहितों के लिए विवाह के अच्छे प्रस्ताव आ सकते हैं। करियर की समस्या मित्र की मदद से सुलझ जाएगी। नई संपत्ति खरीदने की इच्छा पूरी होने के योग हैं।

तुला राशि-आज का दिन खुशनुमा रहेगा। परिवार के पुराने गिले-शिकवे दूर होंगे। महत्वपूर्ण विषयों पर वरिष्ठों की सलाह लें। जीवनसाथी के साथ संबंध मधुर रहेंगे और किसी नई संपत्ति की खरीदारी संभव है। बाहरी लोगों को निजी मामलों में दखल न देने दें।

वृश्चिक राशि - अत्यंत फलदायक दिन है। जरूरी काम पूरा होने से छोटी पार्टी का आयोजन कर सकते हैं। व्यापारिक साख बढ़ेगी और अच्छा प्रदर्शन करेंगे। निवेश संबंधी किसी भी अनजान योजना में पैसा लगाने से बचें, वरना धन फंस सकता है।

धनु राशि- सामान्य दिन रहेगा। विदेश से अच्छी खबर मिल सकती है। लेन-देन में बहुत सावधान रहें, धन फंसने का डर है। स्वभाव में विनम्रता रखें, तभी काम निकल पाएंगे। पार्टनरशिप शुरू करने से पहले पूरी जांच-पड़ताल कर लेना हितकर होगा।

मकर राशि - मध्यम फलदायी दिन है। वाहन चलाते समय सावधानी बरतें, दुर्घटना की आशंका है। संतान के करियर की चिंता दूर होगी। बिजनेस प्लान से मुनाफा होगा, लेकिन जीवनसाथी के साथ अनबन से मानसिक तनाव हो सकता है। एक लक्ष्य निर्धारित करें।

कुंभ राशि- अच्छा दिन रहेगा। सामाजिक और धार्मिक कार्यों में हिस्सा लेंगे। खान-पान की आदतों में सुधार करें, अधिक तला-भुना खाने से पेट की समस्या हो सकती है। परिवार के किसी सदस्य के विवाह की चर्चा आगे बढ़ेगी। करीबियों का सहयोग मिलेगा।

मीन राशि- 8 अप्रैल आपको सावधानी से काम लेने की जरूरत है। खर्चों पर नियंत्रण रखें और जल्दबाजी से बचें। परिवार में तालमेल बनाकर चलें। किसी भी चीज को लेकर ओवरथिंक करने से बचें।

– ज्योतिष गुरु पंडित अतुल शास्त्री

7–8 घंटे की नींद क्यों होती है जरूरी?

जितना जरूरी पेट के लिए खाना होता है उससे भी ज्यादा जरूरी आंखों के लिए नींद होती है, लेकिन आज के जमाने में नींद जैसी बेहद जरूरी चीज को लोग नजरअंदाज कर देते हैं जो कि उनकी सेहत के लिए काफी घातक साबित हो सकता है। देर से सोना और सिर्फ 5-6 घंटे की नींद लेना आजकल एक तरह का नॉर्म बन गया है, इसमें "हसल कल्चर" का भी बड़ा हाथ है, जो कम नींद लेकर ज्यादा काम करने को बढ़ावा देता है, काम के प्रति लगन होना बहुत जरूरी है, लेकिन इसके लिए अपनी नींद से समझौता करना बिल्कुल भी सही नहीं है।

"नींद के दौरान हमारा दिमाग दिनभर की गंदगी (वेस्ट) को साफ करता है और याददाश्त, लर्निंग और इमोशन्स से जुड़ी चीजों को रीसेट करता है, साथ ही शरीर में भूख, मेटाबॉलिज्म और तनाव से जुड़े हार्मोन को भी ठीक करता है, लेकिन जब नींद कम हो जाती है तो शरीर का बैलेंस बिगड़ने लगता है, इसकी वजह से दिनभर थकान, ध्यान न लगना, चिड़चिड़ापन और सोचने की स्पीड धीमी हो सकती है। नींद की कमी का असर दिल, ब्लड प्रेशर और इम्यून सिस्टम पर भी पड़ता है, लंबे समय तक कम नींद लेने से हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और ज्यादा तनाव जैसी समस्याएं हो सकती है। इंसानी शरीर एक घड़ी की तरह काम करता है, जो समय आने पर हमें नींद के संकेत देता है। 7–8 घंटे की नींद शरीर को बैलेंस में रखने और अगले दिन के लिए तैयार करने में अहम भूमिका निभाती है, लेकिन जब नींद कम हो जाती है, तो दिमाग थका हुआ महसूस करता है और रोजमर्रा के काम करना मुश्किल हो जाता है। इसकी वजह से लोगों को मूड स्विंग्स और सिरदर्द जैसी दिक्कतें हो सकती हैं। साथ ही, इसका सीधा असर शरीर की स्ट्रेस और हार्मोन को संभालने की क्षमता पर भी पड़ता है"।

हमारा दिमाग सही तरीके से काम करने के लिए नींद का इस्तेमाल करता है जब हम सोते हैं, तो दिमाग यादों को प्रोसेस करता है और ऊर्जा को फिर से स्टोर करने में मदद करता है, इसलिए जब किसी को जरूरत के हिसाब से नींद नहीं मिलती, तो दिमाग सही से काम नहीं कर पाता, इसकी वजह से सोचने की गति धीमी हो जाती है, ध्यान कमजोर पड़ता है और चीजें भूलने की आदत हो जाती है। वहीं, अगर कोई व्यक्ति रोज एक ही समय पर सोने का रूटीन फॉलो करता है, तो उसे अच्छी नींद आती है और वह ज्यादा एक्टिव, संतुलित और प्रोडक्टिव महसूस करता है।

महंगे कपड़ों की सफाई के टिप्स

महंगे कपड़े हमारी पर्सनैलिटी को निखारते हैं और खास मौकों पर हमारी पहचान बन जाते हैं, लेकिन इन्हें संभालना और सही तरीके से साफ करना बहुत जरूरी होता है, वरना इनकी चमक और क्वालिटी जल्दी खराब हो सकती है। कई लोग महंगे कपड़ों को धोने में गलती कर देते हैं, जिससे कपड़े सिकुड़ जाते हैं या उनका रंग उड़ जाता है। ऐसे में घर पर ही सही और सुरक्षित तरीके अपनाकर आप अपने महंगे कपड़ों को लंबे समय तक नया जैसा रख सकते हैं। कुछ आसान टिप्स अपनाकर आप बिना नुकसान के इनकी सफाई कर सकते हैं।

1. लेबल जरूर पढ़ें

हर महंगे कपड़े पर वॉश के निर्देश दिए होते हैं। पहले लेबल पढ़ें, क्या उसे हाथ से धोना है, ड्राई क्लीन करना है या मशीन में।

2. हल्के डिटर्जेंट का इस्तेमाल करें

हार्ड डिटर्जेंट कपड़े की क्वालिटी खराब कर सकता है। हमेशा माइल्ड या बेबी डिटर्जेंट का उपयोग करें।

3. हाथ से धोना बेहतर होता है

सिल्क, ऊन या डेलिकेट फैब्रिक को मशीन में न डालें। ठंडे पानी में हल्के हाथों से धोएं।

4. ज्यादा रगड़ें नहीं

दाग हटाने के लिए कपड़े को जोर से रगड़ने से कपड़ा खराब हो सकता है। हल्के हाथों से दाग साफ करें।

5. ठंडे पानी का उपयोग करें

गर्म पानी से कपड़ों का रंग उड़ सकता है। हमेशा ठंडे या हल्के गुनगुने पानी का इस्तेमाल करें।

6. प्राकृतिक तरीके अपनाएं

दाग हटाने के लिए नींबू या बेकिंग सोडा का हल्का उपयोग करें यह सुरक्षित और केमिकल-फ्री तरीका है।

7. धूप में सीधे न सुखाएं

तेज धूप से कपड़ों का रंग फीका पड़ सकता है। छांव में सुखाना बेहतर होता है।

पनीर प्रोटीन का बेहतरीन सोर्स

पनीर को शाकाहारियों के लिए प्रोटीन का पावरहाउस माना जाता है। चाहे जिम जाने वाले युवा हों या बढ़ते बच्चे, हर कोई मांसपेशियों की मरम्मत और मजबूती के लिए पनीर पर निर्भर रहता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पनीर को केवल डाइट में शामिल करना ही काफी नहीं है? उसे पकाने का तरीका तय करता है कि आपके शरीर को कितना पोषण मिलेगा। जी हां, अक्सर स्वाद और टेक्सचर के चक्कर में हम रसोई में ऐसी गलतियां कर बैठते हैं, जिससे पनीर का प्रोटीन कम हो जाता है। अगर आप भी पनीर को गलत तरीके से पका रहे हैं, तो आप केवल कैलोरी ले रहे हैं, प्रोटीन नहीं। आइए जानें इन 3 गलतियों के बारे में।

अक्सर पनीर को नरम बनाने के चक्कर में लोग उसे खौलते हुए पानी में डाल देते हैं या बहुत देर तक पानी के साथ उबालते हैं।पनीर के प्रोटीन ज्यादा तापमान के प्रति संवेदनशील होते हैं। जब आप इसे 100C से ऊपर के उबलते पानी में डालते हैं, तो इसके प्रोटीन स्ट्रक्चर का डिनाचुरेशन हो जाता है। इससे पनीर रबड़ जैसा सख्त हो जाता है और उसके भीतर मौजूद विटामिन बी-कॉम्प्लेक्स जैसे पोषक तत्व पानी में घुलकर खत्म हो जाते है। पनीर को कभी भी उबलते पानी में न पकाएं। अगर पनीर सख्त है, तो उसे गुनगुने पानी में 5–10 मिनट के लिए भिगोकर छोड़ दें। इससे वह बिना पोषण खोए नरम हो जाएगा। मटर पनीर हो या कड़ाही पनीर, हम अक्सर पनीर के टुकड़ों को सुनहरा होने तक तेल में डीप फ्राई करते हैं। स्वाद में तो यह लाजवाब लगता है, लेकिन सेहत के लिहाज से यह सबसे बड़ी भूल है। डीप फ्राई करने से पनीर की बाहरी परत सख्त हो जाती है, जिसे पचाना शरीर के लिए मुश्किल होता है। ज्यादा तापमान पर तलने से पनीर में मौजूद गुड फैट्स ऑक्सीडाइज हो जाते है और प्रोटीन की गुणवत्ता गिर जाती है। साथ ही, यह पनीर की कैलोरी को 2 से 3 गुना बढ़ा देता है, जिससे वजन घटने के बजाय बढ़ने लगता है। पनीर को तलने के बजाय सौटे करें। इससे स्वाद भी बरकरार रहेगा और प्रोटीन भी।

स्टोर करने का तरीका

पनीर एक जल्दी खराब होने वाला फूड है। अगर पनीर को बिना ढके खुला रख दें या बहुत दिनों तक स्टोर करने से उसमें बैक्टीरिया पनपने शुरू हो जाते हैं और उसका प्रोटीन कम होने लगता है। इससे फूड पॉइजनिंग का खतरा भी रहता है। पनीर को हमेशा एक कटोरे में साफ पानी भरकर उसमें डुबोकर रखें और फिर फ्रिज में रखें। पानी को हर 24 घंटे में बदलते रहें। इससे पनीर 2-3 दिनों तक ताजा और प्रोटीन से भरपूर रहेगा।

दुर्ग–हुडको मार्ग को जोड़ने अंडरब्रिज की मांग, महापौर ने डिप्टी सीएम अरुण साव को सौंपा पत्र

दुर्ग: शहर की यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने और रायपुर नाका से हुडको भिलाई की राह आसान करने के लिए महापौर अलका बाघमार ने बड़ी पहल की है। गुरुवार को महापौर ने उपमुख्यमंत्री एवं नगरीय प्रशासन मंत्री श्री अरुण साव से सौजन्य भेंट की और दुर्ग फ्लाईओवर के नीचे एक नए अंडरब्रिज निर्माण की मांग को लेकर औपचारिक मांग पत्र सौंपा।

यातायात का संतुलन सुधारने की कवायद- सौंपे गए पत्र में महापौर ने स्पष्ट किया कि वर्तमान में दुर्ग से भिलाई की ओर जाने वाले फ्लाईओवर के नीचे केवल एक दिशा में ही अंडरब्रिज की सुविधा है। दूसरी ओर, हुडको कॉलोनी की ओर जाने के लिए सीधा मार्ग न होने से नागरिकों को लंबा चक्कर लगाना पड़ता है। इससे न केवल समय की बर्बादी होती है, बल्कि ईंधन की खपत भी बढ़ रही है।

जाम और दुर्घटनाओं से मिलेगी मुक्ति- स्थानीय नागरिकों और राहगीरों को रायपुर नाका पार कर हुडको जाने में होने वाली दिक्कतों को देखते हुए यह मांग की गई है। तेजी से विकसित हो रहे इस क्षेत्र में वाहनों का दबाव बढ़ रहा है, जिससे अक्सर जाम की स्थिति बनी रहती है। महापौर ने मंत्री को अवगत कराया कि यदि इस दिशा में अंडरब्रिज का निर्माण होता है, तो शहर की यातायात व्यवस्था अधिक व्यवस्थित और सुरक्षित हो जाएगी।

मंत्री ने दिया सकारात्मक आश्वासन- नगरीय प्रशासन मंत्री श्री अरुण साव ने महापौर की मांग पर गंभीरता दिखाते हुए सकारात्मक विचार करने का आश्वासन दिया है। मुलाकात के दौरान महापौर अलका बाघमार ने दुर्ग शहर के अन्य विकास कार्यों और अधोसंरचना परियोजनाओं पर भी विस्तार से चर्चा की। इस परियोजना के स्वीकृत होने से दुर्ग और भिलाई के बीच का सफर काफी आसान हो जाएगा।

वरिष्ठ कांग्रेस नेत्री मोहसिना किदवई के निधन पर गाजीपुर में शोक

गाजीपुर। पूर्व केंद्रीय मंत्री, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व सांसद, कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री मोहसिना किदवई जी के निधन का समाचार अत्यंत दुखद है। उनके निधन पर आज9 अप्रैल को दोपहर 1:00 बजे कैंप कार्यालय सकलेनाबाद में जिला एवं शहर कांग्रेस कमेटी द्वारा एक शोक सभा आयोजित की गई।

शोक सभा में उपस्थित कांग्रेस पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर दो मिनट का मौन रखकर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। इस दौरान सभी ने उनके योगदान को याद करते हुए गहरी शोक संवेदना व्यक्त की। जिला अध्यक्ष सुनील राम ने कहा कि मोहसिना किदवई जी का निधन कांग्रेस पार्टी के लिए अपूरणीय क्षति है। उन्होंने अपना पूरा जीवन जनसेवा और संगठन को मजबूत करने में समर्पित किया। उनका सादगीपूर्ण जीवन और संघर्षशील व्यक्तित्व हम सभी के लिए प्रेरणा है।

शहर अध्यक्ष संदीप विश्वकर्मा ने कहा कि मोहसिना किदवई जी एक मजबूत एवं संवेदनशील नेतृत्व की प्रतीक थीं। उन्होंने हमेशा समाज के कमजोर वर्गों और महिलाओं के उत्थान के लिए कार्य किया। उनका जाना राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र की अपूरणीय क्षति है।

पूर्व विधायक अमिताभ अनिल दुबे ने कहा कि मोहसिना किदवई जी ने अपने लंबे राजनीतिक जीवन में उच्च आदर्श स्थापित किए। उन्होंने हमेशा सिद्धांतों की राजनीति की और संगठन के प्रति उनकी निष्ठा अद्वितीय रही। उनका योगदान सदैव स्मरणीय रहे। डॉ. मार्कण्डेय सिंह एवं एआईसीसी सदस्य रविकांत राय ने कहा कि मोहसिना किदवई जी का जीवन संघर्ष, सेवा और समर्पण की मिसाल है। उन्होंने देश की महिलाओं को राजनीति में आगे बढ़ने का मार्ग दिखाया। उनका निधन हम सभी के लिए गहरा आघात है।

अंत में सभी उपस्थित कांग्रेसजनों ने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हुए उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया।

शोक सभा में प्रमुख रूप से परवेज खां अजय कुमार श्रीवास्तव चंद्रिका सिंह हामिद अली शहजादे सिद्दकी राम नगीना पांडे आलोक यादव राशिद भाई रईस अहमद ओम प्रकाश यादव आलोक यादव राजेश उपाध्याय ओम प्रकाश पासवान जेपी पांडे विनोद सिंह शशिकांत श्रीवास्तव विंध्याचल कुशवाहा दिनेश प्रताप सिंह देवेंद्र सिंह मिंटू खान आदि लोग उपस्थित रहे

भिलाई निगम का स्वच्छता अभियान तेज, तालाबों और नालों की युद्धस्तर पर सफाई

भिलाईनगर। नगर पालिक निगम भिलाई द्वारा शहर को स्वच्छ, सुंदर एवं व्यवस्थित बनाने के उद्देश्य से व्यापक स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत शहर के तालाबों और बड़े-छोटे नालों की युद्धस्तर पर सफाई की जा रही है। निगम आयुक्त राजीव कुमार पाण्डेय के निर्देशानुसार यह अभियान लगातार जारी है। शहर के सभी पांचों जोन क्षेत्रों में अधिकारी एवं कर्मचारी मैदानी स्तर पर सक्रिय रहते हुए सफाई कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आवश्यकता के अनुसार संसाधनों की व्यवस्था कर कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जा रहा है। अभियान के तहत तालाबों से गाद निकालने, जमा कचरे को हटाने तथा नालों की गहन सफाई पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इससे न केवल शहर की स्वच्छता में सुधार होगा, बल्कि जल निकासी व्यवस्था भी सुचारू रूप से संचालित हो सकेगी, जिससे बारिश के दौरान जलभराव की समस्या में कमी आने की संभावना है। निगम प्रशासन स्वच्छ सर्वेक्षण को ध्यान में रखते हुए शहर की स्वच्छता रैंकिंग को बेहतर बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। अधिकारियों का लक्ष्य है कि भिलाई शहर स्वच्छता के क्षेत्र में उत्कृष्ट स्थान प्राप्त करे और नागरिकों को स्वच्छ एवं स्वस्थ वातावरण उपलब्ध हो सके। निगम प्रशासन ने शहरवासियों से अपील की है कि वे भी इस अभियान में सहयोग करें। कचरा निर्धारित स्थान पर ही डालें, गंदगी फैलाने से बचें और स्वच्छता बनाए रखने में अपनी जिम्मेदारी निभाएं।

दुर्ग पुलिस का अवैध कारोबार पर कड़ा प्रहार: शराब और पशु तस्करी में शामिल 3 वाहन राजसात

दुर्ग: जिला पुलिस और प्रशासन ने अवैध गतिविधियों में शामिल अपराधियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए बड़ी कार्रवाई की है। जिलाधीश दुर्ग ने पुलिस के प्रतिवेदन पर सुनवाई करते हुए अवैध शराब परिवहन और पशु तस्करी में प्रयुक्त तीन वाहनों को राजसात (सरकारी संपत्ति घोषित) करने का आदेश जारी किया है।

पुराने मामलों में हुई बड़ी कार्रवाई- यह कार्रवाई थाना जामुल और थाना रानीतराई में दर्ज अलग-अलग प्रकरणों के आधार पर की गई है। पुलिस ने इन मामलों में न केवल आरोपियों को गिरफ्तार किया था, बल्कि अपराध में इस्तेमाल की गई गाड़ियों को भी अपनी कस्टडी में लिया था।

इन वाहनों पर गिरी गाज: आइसर (CG-07/BS-1180): वर्ष 2021 में थाना जामुल पुलिस ने इस वाहन को भारी मात्रा में अवैध शराब का परिवहन करते हुए पकड़ा था।

पिक-अप (CG-07/CN-2670): सितंबर 2024 में जामुल पुलिस ने इसे मवेशियों की तस्करी करते हुए जब्त किया था।

अशोक लीलैंड ट्रक (P-11/CT-5490): अप्रैल 2024 में रानीतराई पुलिस ने इस ट्रक के जरिए की जा रही पशु तस्करी का भंडाफोड़ किया था।

कलेक्टर ने जारी किए आदेश- दुर्ग पुलिस द्वारा ठोस साक्ष्यों के साथ प्रस्तुत किए गए प्रतिवेदन पर जिलाधीश ने मुहर लगा दी है। अब ये तीनों वाहन शासन के अधीन होंगे। इस कार्रवाई से जिले के अवैध शराब तस्करों और पशु तस्करों में हड़कंप मच गया है।

पुलिस की प्रभावी निगरानी- एसपी दुर्ग के निर्देशन में थाना जामुल और रानीतराई पुलिस की टीम ने इन मामलों में प्रभावी विवेचना की, जिसके फलस्वरूप वाहनों को राजसात कराने में सफलता मिली। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि भविष्य में भी ऐसी अवैध गतिविधियों में शामिल संपत्तियों के खिलाफइसी तरह की कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी।

धमधा में दो लंगूरों का शिकार करने वाला आरोपी गिरफ्तार, एयर गन जब्त

दुर्ग: वन्यजीवों के खिलाफ अपराध करने वालों पर नकेल कसते हुए दुर्ग वन विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। धमधा क्षेत्र के ग्राम दनिया (बोरी) में दो लंगूरों का एयर गन से शिकार करने वाले मुख्य आरोपी अजय पटेल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है।

सूचना पर दी गई दबिश- प्राप्त जानकारी के अनुसार, 7 अप्रैल को विभाग को सूचना मिली थी कि ग्राम दनिया में वन्यजीवों का अवैध शिकार किया गया है। सूचना पर त्वरित संज्ञान लेते हुए वन विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने मौके पर दबिश दी। जांच में पाया गया कि आरोपी अजय पटेल, पिता लुमन पटेल ने एयर गन का इस्तेमाल कर दो लंगूरों (सेम्नोपिथेकस एंटेलस) की जान ली है।

कानूनी शिकंजा: अनुसूची-2 का संरक्षित जीव है लंगूर- उल्लेखनीय है कि लंगूर वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची-02 के अंतर्गत एक संरक्षित वन्यजीव है। इस गंभीर अपराध पर वन विभाग दुर्ग ने अधिनियम की धारा 9, 39 एवं 51 के तहत वन अपराध प्रकरण क्रमांक 6983/17 पंजीबद्ध किया है।

गिरफ्तारी के बाद आरोपी अजय पटेल को आज माननीय न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी को 21 अप्रैल तक की न्यायिक रिमांड पर जेल भेजने का आदेश दिया है।

वन विभाग के अधिकारियों ने कड़ा संदेश देते हुए कहा है कि वन्यजीवों के विरुद्ध किसी भी प्रकार की क्रूरता या अपराध को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भविष्य में भी शिकारियों और अवैध गतिविधियों में संलिप्त लोगों के खिलाफऐसी ही सख्त दंडात्मक कार्रवाई जारी रहेगी।

शालिनी पटेल भगवा पार्टी भिलाई शहर अध्यक्ष नियुक्त

दुर्ग /भिलाई – भगवा पार्टी छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष देवेश मिश्रा ने सशक्त एवं दबंग हिन्दू नेत्री शालिनी पटेल को भगवा पार्टी भिलाई शहर अध्यक्ष नियुक्त किया है।

यह नियुक्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवाकांत शुक्ला की अनुमति एवं प्रदेश भगवा कार्यकारिणी छत्तीसगढ़ की अनुशंसा से की गई है।प्रदेश अध्यक्ष देवेश मिश्रा ने नवनियुक्त अध्यक्ष शालिनी पटेल को बधाई देते हुए कहा है कि वे बहुत ही दमदार और जनसमस्याओ को निडरता से उठाने वाली और नारी शक्ति के लिए लगातार कार्य करने वाली नेत्री है। उनके नेतृत्व में भिलाई में भगवा पार्टी का परचम लहराएगा। श्री मिश्रा ने शालिनी पटेल को तत्काल

प्रभाव से भगवा (भारतीय गण वार्ता)पार्टी के उद्देश्यों,रीति नीति व कार्यक्रमों को जन जन तक पहुंचाने,पार्टी संगठन को मजबूती प्रदान करने एवं जन कल्याण हेतु कार्य प्रारम्भ कर देने निर्देशित किया है। शालिनी पटेल की इस नियुक्ति पर प्रदेश संगठन के उपाध्यक्ष अतुल नंद शुक्ला,हिरेन्द्र कुमार साहू,महासचिव ज्ञानेश्वर ताम्रकार,आकाश दुबे,प्रदेश सचिव मीना बिष्ट एवं वरुणेशवर पाण्डेय,प्रियंक सोनी,मनहरण साहू,भागवत देवांगन,ओमप्रकाश सोनी,मनोज गुप्ता,मेघराज कोटवानी ने बधाई दी है।

नवनियुक्त भिलाई शहर अध्यक्ष ने कहा कि हम पूरे भिलाई शहर में हमारे भगवा पार्टी की रीति नीति के अनुसार भगवा सत्ता लहराएगे और हर स्तर पर सनातनी परिवारों को मजबूत करने,उन्हें एकजुट रखने,उन्हें नेतृत्व प्रदान करने कार्य करेगी।

स्कूलों में बायोमेट्रिक अपडेट कार्य शीघ्र पूरा करें: कलेक्टर अभिजीत सिंह

जनगणना कार्य में लगे अधिकारी व कर्मचारियों को विशेष परिस्थितियों में ही मिलेगा अवकाश

दुर्ग। कलेक्टर अभिजीत सिंह ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित समय-सीमा की बैठक में जनगणना कार्य को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जनगणना कार्य के लिए प्रगणक और पर्यवेक्षकों को समय पर प्रशिक्षण दिया जाना अनिवार्य है। इसके लिए इंचार्ज अधिकारियों को प्रशिक्षण हेतु उपयुक्त भवनों का चयन कर प्रशिक्षण सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि जिन अधिकारी-कर्मचारियों की ड्यूटी जनगणना कार्य में लगाई गई है, उनका अवकाश स्वीकृत विशेष परिस्थितियों में ही किया जाए। उन्होंने बताया कि जनगणना दो चरणों में आयोजित होगी। पहला चरण 1 मई से 30 मई 2026 तक मकान सूचीकरण एवं गणना का होगा, जबकि दूसरा चरण फरवरी 2027 में परिवारों की व्यक्तिगत जानकारी एकत्रित करने के लिए किया जाएगा। बैठक में ग्राम पंचायतों में राजस्व संबंधी कार्यों की भी समीक्षा की गई।

कलेक्टर ने अविवादित नामांतरण, बंटवारा और पंजीयन प्रक्रिया को तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए। सभी पंचायतों में पंजीयन कार्य प्रारंभ हो चुका है, लेकिन जहां अब तक कार्य शुरू नहीं हुआ है, वहां के सचिवों का वेतन रोकने के निर्देश दिए। साथ ही जिन पंचायतों में प्रकरण दर्ज हो चुके हैं, वहां संबंधित एसडीएम को नियमित समीक्षा कर त्वरित निराकरण सुनिश्चित करने को कहा गया। कलेक्टर सिंह ने जिले में विद्यार्थियों के बायोमेट्रिक अपडेट कार्य की भी समीक्षा की। कलेक्टर के मार्गदर्शन में शासकीय और निजी स्कूलों में यह कार्य निरंतर जारी है। वर्तमान में कई स्कूलों में परीक्षाएं चल रही हैं और कुछ में समाप्त हो चुकी हैं, जिसके कारण विद्यार्थियों की उपस्थिति कम है। इस स्थिति को देखते हुए कलेक्टर ने शिक्षा विभाग को निर्देश दिए कि स्कूल प्राचार्यों के साथ समन्वय स्थापित कर निःशुल्क बायोमेट्रिक अपडेट कार्य को शीघ्र पूर्ण कराए। बैठक में एडीएम वीरेन्द्र सिंह, अपर कलेक्टर योगिता देवांगन, नगर निगम भिलाई के आयुक्त राजीव पाण्डेय, नगर निगम दुर्ग आयुक्त सुमित अग्रवाल, नगर निगम रिसाली की आयुक्त मोनिका वर्मा, संयुक्त कलेक्टर हरवंश सिंह मिरी एवं सिद्धी थॉमस सहित सभी एसडीएम एवं जनपद सीईओ और समस्त विभाग के जिला प्रमुख अधिकारी उपस्थित थे।

पावर हाउस में धारदार हथियार लहराकर लोगों को डराने वाला युवक गिरफ्तार

भिलाई: छावनी थाना पुलिस ने पावर हाउस इलाके में दहशत फैलाने वाले एक युवक को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी सार्वजनिक स्थान पर धारदार हथियार लहराकर राहगीरों को डरा-धमका रहा था। पुलिस ने आरोपी के पास से हथियार जब्त कर उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है।

मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई- पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, गुरुवार को छावनी पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि पावर हाउस स्थित सुलभ शौचालय के पास एक युवक हाथ में घातक हथियार लिए आने-जाने वाले लोगों को डरा रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस की एक विशेष टीम मौके पर पहुंची और घेराबंदी कर युवक को घर दबोचा।

आरोपी की पहचान और कानूनी कार्रवाई- पकड़े गए आरोपी की पहचान पवन महानंद (24 वर्ष) के रूप में हुई है, जो कैंप 02, जलेबी चौक (कमला पब्लिक स्कूल के पीछे) का निवासी है। पुलिस ने उसके कब्जे से एक धारदार हथियार बरामद किया है।

थाना प्रभारी ने बताया कि आरोपी का उद्देश्य सार्वजनिक स्थान पर भय का माहौल पैदा करना था। पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध आर्म्स एक्ट की धारा 25 और 27 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को विधिवत रूप से न्यायालय में पेश किया गया।

पुलिस टीम की सराहना- सरेराह हथियार लहराने वाले अपराधी को तत्काल पकड़ने में छावनी पुलिस स्टाफ की भूमिका सराहनीय रही। इस त्वरित कार्रवाई से क्षेत्र के नागरिकों ने राहत की सांस ली है।

आवासीय विद्यालय में निःशुल्क अध्ययन के लिए आवेदन 23 अप्रैल तक आमंत्रित

दुर्ग। मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति तथा जनजाति विद्यार्थी उत्कर्ष योजना (पूर्व में जवाहर उत्कर्ष योजना) अंतर्गत अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति वर्ग के ग्रामीण प्रतिभावान विद्यार्थियों को गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना, नयी सोच के साथ बेहतर कॅरियर चयन का अवसर प्रदान करते हुए प्रतिस्पर्धी बनाना तथा बहुमुखी व्यक्ति त्व विकास के लिए अवसर प्रदान करना है। इस योजना अंतर्गत विद्यार्थी को कक्षा 6वीं से 12वीं तक छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित उत्कृष्ट आवासीय विद्यालय में अध्ययन की निःशुल्क सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। चयनित उत्कृष्ट विद्यालय को विभाग द्वारा निर्धारित मान्य शुल्क की प्रतिपूर्ति किया जाएगा।

स्वामी, मुद्रक व प्रकाशक संजय तिवारी द्वारा असमा पब्लिशर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ग्रास मेमोरियल सेंटर के बाजू, जयस्तंभ चौक, रायपुर (छ.ग.)-492001 से मुद्रित करवाकर व गदा चौक, फरीद नगर रोड स्वर्गीय तुलाराम मेमोरियल स्कूल के पास सुपेला भिलाई, जिला- दुर्ग (छ.ग.) पिन कोड-490023 से प्रकाशित। संपादक : संजय तिवारी, मो. 9200000214 (समाचार चयन के लिए पीआरबी एक्ट के तहत जिम्मेदार), समस्त विवादों का निपटारा न्यायलीन क्षेत्र दुर्ग होगा। डाक पंजीयन क्रमांक- सीजी/दुर्ग/लोकतंत्र प्रहरी/2026-28, Email : loktantraprahrinews@gmail.com